उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विज्ञापन मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

सच का साथी..

बी पी एस न्यूज

www.bpsnews.in

(वर्ष-10 अंक-23

पृष्ठ 8 मूल्य 2/रुपया

सोमवार 07 जुलाई 2025

पुलिस कमिश्नर अधिवक्ता चुनावों में उच्च न्यायालय के निर्देशो का कराए पालन : पं रवीन्द्र शर्मा 8

जनता की कमाई से बना जेपीएनआईसी अखिलेश की जागीर नहीं: ब्रजेश पाठक 6

पुलिस को जेल में बंद गैंगस्टर पर शक, राहुल गांधी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना

पटना। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की सरेआम गोली मारकर हत्या किए जाने ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भाजपा और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को भारत की अपराध राजधानी बना दिया है। उन्होंने कहा, आज बिहार लूट, गोली और हत्या के साए में जी रहा है। अपराध यहां आम बात हो गया है और सरकार पूरी तरह नाकाम है। कांग्रेस नेता ने कहा, बिहार के भाइयो और बहनो यह अन्याय अब और नहीं सहा जा सकता। जो सरकार आपके बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकती वह आपके भविष्य की जिम्मेदारी भी नहीं ले सकती। उन्होंने कहा, हर हत्या, हर लूट, हर गोली- एक चीख है बदलाव की। अब वक्त है एक नए बिहार का जहां डर नहीं, तरक्की हो। इस बार वोट सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बिहार को बचाने का है।

पटना के जाने-माने कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या की जांच कर रही बिहार पुलिस को अब बेउर जेल में बंद गैंगस्टर अजय वर्मा की संलिप्तता का संदेह है। शुक्रवार रात को खेमका को उनके घर के पास बाइक सवार हमलावरों ने गोली मार दी थी। खेमका के छोटे बेटे गौरव खेमका ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। सूत्रों के अनुसार, बिहार पुलिस के बड़े अधिकारियों ने बेउर जेल में छापा मारकर अजय वर्मा से पूछताछ भी की है। पुलिस को शक है कि यह हत्या ज़मीन विवाद के चलते कॉन्ट्रैक्ट किलिंग (किराए पर हत्या) का मामला है। गोपाल खेमका, जो राज्य के सबसे पुराने निजी अस्पतालों में से एक मगध अस्पताल के मालिक थे, उन्हें शुक्रवार रात पॉश गांधी मैदान इलाके में उनके घर पंचे होटल के पास एक अपार्टमेंट के सामने कार से उतरते ही गोली मार दी गई थी। बता दें, सात साल पहले हाजीपुर में बदमाशों ने उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

पुलिस अधीक्षक (पटना मध्य) दीक्षा ने संवाददाताओं से कहा, स्थानीय थाने के अधिकारी एवं गश्ती वाहनों में सवार पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक विशेषज्ञ साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं। जांच जारी है। उन्होंने कहा, घटनास्थल से गोली और कारतूस मिले हैं। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गोपाल खेमका को मोटरसाइकिल सवार एक अज्ञात हमलावर ने गोली मारी। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने व्यवसायी के शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, यह सिर्फ हत्या नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास है। दुख की इस घड़ी में हम सभी पीड़ित परिवार के साथ हैं। इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। कानून को अपने हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जरूरत पड़ी तो मुठभेड़ का भी सहारा लिया जाएगा। उन्होंने कहा, राज्य में फरार अपराधियों की संपत्ति भी ध्वस्त की जा रही है। पुलिस और प्रशासन को अपराधियों से निपटने के लिए खुली छूट दी गई है।% उन्होंने कहा कि अपराधियों की पहचान कर ली गयी है तथा उन्हें शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि इस घटना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की और उस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को गोपाल खेमका हत्याकांड की जांच शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया। गोपाल खेमका कथित रूप से भाजपा से संबद्ध थे। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कानून व्यवस्था राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और लापरवाही बरतने पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बयान में कहा गया, नीतीश ने संबंधित अधिकारियों को खेमका की हत्या के मामले की जांच जल्द से जल्द पूरी करने का निर्देश दिया।

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भरी 'भगवा-ए-हिंद' की हुंकार, रामभद्राचार्य ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की उठाई मांग

बिहार की धरती पर सनातन के महाकुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें संतों ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की हुंकार भरी। संतों के हिंदु राष्ट्र की हुंकार से पटना की धरती गूंज उठी। गांधी मैदान से गर्जना करते हुए बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि कुछ लोग तिरंगे पर चांद चाहते हैं और हम चांद पर तिरंगा चाहते हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा कि हम 'गजवा-ए-हिंद नहीं, 'भगवा-ए-हिंद' चाहते हैं।

बिहार की धरती से सनातनी उद्घोष हुआ है। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान सनातन धर्म की आस्था, अध्यात्म और परंपरा का जीवंत प्रतीक बन गया। यहां देशभर से आए संत-महात्मा, महामंडलेश्वर और जगद्गुरुओं ने सनातन महाकुंभ 2025 में भाग लिया और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की।

भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर, आयोजित किए सनातन महाकुंभ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हमें भरोसा है की अगर भारत हिन्दू राष्ट्र बनेगा, तो पहला राज्य बिहार ही होगा।

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने सनातन की महिमा का बखान करते हुए कहा, 'हम भाग्यशाली हैं कि पहला हमें तन मिला, दूसरा हमें भारत राष्ट्र मिला और तीसरा सनातन धर्म मिला।' बाबा बागेश्वर ने जातिवाद का जहर घोलने वालों से भी लोगों को सावधान रहने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि देश को जातपात नहीं, राष्ट्रवाद के लिए लड़ना है। उन्होंने ऐलान किया कि बिहार में चुनाव के बाद सनातनियों को जोड़ने के लिए पदयात्रा करूंगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि मैं किसी एक पार्टी का नहीं हूं, जिस पार्टी में हिंदू हैं उसी पार्टी का मैं हूं। पटना में सनातन महाकुंभ में शामिल होने आए तुलसी पीठाधीश्वर, जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य भी विरोधियों पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि बिहार के कुछ नेताओं ने संत समाज का अपमान किया है। हमने आपका क्या लिया, आप तो जानवरों का चारा तक खा गए। पटना की धरती से जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने भी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग उठाई। जगद्गुरु ने कहा कि सनातन संकल्प का नाम है। जो यहां वंदे भारत कहेगा, वही इस धरती पर राज करेगा।

मंडी में बादल फटने के बाद पूरा परिवार लापता; केवल दस महीने की बच्ची जिंदा बची

मंडी जिले के तलवारा गांव में बादल फटने की घटना में दस महीने की नितिका के परिवार के तीन सदस्य या तो बह गए या उनकी मृत्यु हो गई और वह संभवत: अपने परिवार की अकेली जीवित सदस्य रह गयी है।मंगलवार को जब गांव में बादल फटा तब बच्ची के 31 वर्षीय पिता रमेश कुमार अपने घर के अंदर घुस रहे पानी को रोकने की कोशिश कर रहे थे तभी बादल फटने से गांव में तबाही मच गई। उनका शव मलबे में मिला। नितिका की मां राधा देवी (24) और दादी पुर्णू देवी (59) रमेश की तलाश में निकल पड़ीं। दोनों महिलाओं का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

पड़ोसी प्रेम सिंह ने बच्ची को अकेले रोते हुए देखा और उसे रमेश के चचेरे भाई बलवंत के पास ले गए। बलवंत पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के निजी सुरक्षा अधिकारी हैं। बलवंत ने पीटीआई- को बताया, बच्ची हमारे पास है।

उन्होंने कहा कि उप-विभागीय मजिस्ट्रेट ने बच्ची के नाम पर बैंक खाता खोलने की पेशकश की है और यह खाता कल खोला जाएगा। बलवंत ने कहा, उन्होंने (एसडीएम ने) कहा कि बहुत सारी कॉल आ रही हैं और लोग इस त्रासदी के बारे में सुनने के बाद बच्ची की मदद के लिए आगे आ रहे हैं।बादल फटने से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र पवारा, थुनाग, बैदशाड़, कंडा और मुराद हैं। इन सभी पंचायतों में भारी तबाही हुई है, जहां सड़क, पानी और बिजली योजनाओं को काफी नुकसान पहुंचा है।अधिकारियों ने बताया कि मंडी जिले में बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की दस घटनाओं में अब तक चौदह लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 31 लापता लोगों की तलाश जारी है। बलवंत ने बताया कि रमेश ने भी मात्र छह महीने की उम्र में अपने पिता को खो दिया था।रमेश एक किसान था जिसकी कमाई अच्छी नहीं थी और घर के खर्च के लिए उसे पुर्नू देवी की तनख्वाह पर निर्भर रहना पड़ता था।

मोहर्रम जुलूस के दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आया ताजिया, करंट से झुलसे शख्स की मौत; कई घायल

दरभंगा। दरभंगा जिले के तारडीह प्रखंड के ककोढ़ा गांव में मुहर्रम के दौरान चौकी मिलान के वक्त बिजली की हाई टेंशन तार के चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि इस घटना में करीब तीन दर्जन लोग झुलस गए है। इनका विभिन्न अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। गम्भीर रूप से झुलसे पांच लोगों को बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान मो मेराज के रूप में की गई है। घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि ककोधा गांव में तीन गांव के लोग ताजिया मिलान कर रहे थे। ताजिया लेकर सड़क किनारे से गुजर रहे भीड़ में ताजिया ऊपर से गुजर रहे 11 हजार हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गए। देखते ही देखते एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 50 लोग झुलसकर सड़क पर गिर गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को तत्काल पास के अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाजरत पांच लोगों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है। घायलों में श्रवण कुमार साहू, सुरेश महतो, मो हारून, मो साजिद, मो बिस्मिल और मो रहमत सहित कई लोग शामिल हैं। पंचायत के मुखिया श्रवण कुमार ने बताया कि हरेक वर्ष आज के दिन बिजली काट दिया जाता था। इस वर्ष विभाग के अधिकारियों ने बिजली नहीं कटवाया। ताजिया मिलान के दौरान 11 हजार हाई वोल्टेज की चपेट में आने एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि लगभग 50 लोग झुलस गए है। तारडीह की बीडीओ प्रीति कुमारी ने बताया कि करेंट की चपेट में आने से 25 लोग घायल हुए है। सभी का इलाज चल रहा है।

शरबत पीने और खाद्य पदार्थ खाने से एक व्यक्ति की मौत, 75 से ज्यादा बीमार

सहारनपुर जिले के नानौता क्षेत्र में मुहर्रम के मौके पर कथित रूप से दूषित शरबत पीने और अन्य चीजें खाने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी तथा 75 से ज्यादा लोग बीमार हो गये। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान नानौता थाना क्षेत्र के शेखजादगान मोहल्ले के निवासी शबी हैदर (60) के रूप में हुई है। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि शनिवार शाम नानौता कस्बे के एक मोहल्ले में मुहर्रम के मातमी जुलूस के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बिरयानी और शरबत का सेवन किया था जिसके बाद करीब 75 लोगों को उल्टियां होने लगीं एवं अन्य समस्याएं हुईं।बंसल ने बताया कि उन्हें तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि खाद्य विषाक्तता के शिकार हुए शबी हैदर को उपचार के लिये चिकित्सा केंद्र ले जाया जा रहा था लेकिन उसने रास्ते में दम तोड़ दिया।बंसल ने बताया कि जुलूस के मौके पर इस्तेमाल की गयी खाने-पीने की चीजों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं और मरीजों को जरूरी चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं।

पहचान छिपाकर व्यवसाय करना हर दृष्टि से गलत: बाबा स्वामी रामदेव

कांवड़ यात्रा मार्ग पर खान-पान की दुकानों पर अपना नाम प्रदर्शित किये जाने का समर्थन करते हुए योग गुरु बाबा स्वामी रामदेव ने रविवार को कहा कि पहचान छिपाकर व्यवसाय करना हर दृष्टि से गलत है। रामदेव ने यहां कहा कि उन्हें अपने हिंदू और सनातनी होने पर गर्व है, ठीक उसी तरह मुसलमानों को भी अपने मुसलमान होने पर गर्व होना चाहिए।उन्होंने पूछा, ''आखिर क्या वजह है कि मुसलमान नाम छिपाकर कांवड़ यात्रा में व्यवसाय कर रहे हैं। पहचान छिपाना नैतिक और धार्मिक, हर दृष्टि से गलत है।'' रामदेव ने कहा कि यह तो ग्राहक को तय करना है कि वह किसकी दुकान पर जाएं।उन्होंने कहा,''मुझे जैसे हिन्दू और सनातनी होने पर गर्व है उसी तरह से मुसलमानों को भी मुसलमान होने पर गर्व होना चाहिए।'' रामदेव ने कहा कि उनके

(मुसलमानों के) भी पूर्वज हिंदू थे। महाराष्ट्र में हिंदीभाषियों के साथ मारपीट किये जाने को योग गुरु ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

ब्रिक्स के संयुक्त घोषणा-पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा, भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक सफलता

नई दिल्ली। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 भारत के लिए एक बड़ी राजनयिक जीत लेकर आया, जब सम्मेलन के संयुक्त घोषणा-पत्र में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी और कई घायल हुए थे।

संयुक्त घोषणा-पत्र में कहा गया कि आतंकवाद किसी भी रूप में, उद्देश्य या औचित्य के साथ स्वीकार्य नहीं है। इसमें यह भी जोड़ा गया कि आतंकवाद को किसी धर्म, नस्ल, राष्ट्रीयता या सभ्यता से नहीं जोड़ा जा सकता और सभी आतंकी संगठनों एवं उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए।

पहलगाम हमले को अत्यंत निंदनीय और गंभीर अपराध करार देते हुए ब्रिक्स ने पहली बार इतने स्पष्ट शब्दों में भारत में हुए किसी आतंकी हमले की आलोचना की है। इस बयान को भारत की कूटनीतिक रणनीति की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार की मांग को फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक संस्थाएं अब समकालीन वास्तविकताओं और विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को प्रभावी ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर पा रही हैं। यह सुझाव दिया गया कि परिषद की संरचना में बदलाव कर इसे अधिक समावेशी और लोकतांत्रिक बनाया जाए।

इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस मंच से आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक नेतृत्व को खुलकर संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से निशाना साधा और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के सामूहिक कार्रवाई की अपील की।प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में दोहराया कि आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति ही एकमात्र विकल्प है और इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई भी देश तटस्थ नहीं रह सकता।

आज 90वां जन्मदिन मना रहे दलाई लामा, जानिए तिब्बत छोड़कर भारत में क्यों रहते हैं

सिक्किम। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा आज यानी की 06 जुलाई को अपना 90वां जन्मदिन मना रहे हैं। भले ही वह खुद को एक साधारण भिक्षु मानते हैं, लेकिन वह 60 से अधिक सालों से तिब्बत के लोगों और उनके हितों को लेकर अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बनाए रखने में कामयाब रहे।

हालांकि उनके इस मिशन की कर्मभूमि भारत ही रहा है। दरअसल दलाई लामा उनका नाम नहीं बल्कि उनका पद है। वह 14वें दलाई लामा हैं। उनका असल नाम ल्हामो धोंडुप था। तो आइए जानते हैं उनके बर्थडे के मौके पर 14वें दलाई लामा के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में...

किंघई के उत्तर-पश्चिमी चीनी प्रांत में 06 जुलाई 1935 को एक किसान परिवार में ल्हामो धोंदुप का जन्म हुआ था। एक खोज दल ने उनको तिब्बत के आध्यात्मिक और लौकिक नेता वा 14वां अवतार माना था, उस दौरान वह 2 साल के थे। वहीं साल 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। हालांकि इस कब्जे को चीन ने %शांतिपूर्ण मुक्ति% कहा था।इस घटना के कुछ समय बाद ही किशोर दलाई लामा ने एक राजनीतिक भूमिका निभाई थी। इस दौरान उन्होंने माओत्से तुंग और अन्य चीनी नेताओं से मिलने के लिए बीजिंग की यात्रा की। वहीं 9 साल बाद डर से कि उनका अपहरण किया जा सकता है। तिब्बत में एक बड़े विद्रोह को बढ़ावा मिला था। तिब्बत में किसी भी विद्रोह को दबाने के लिए चीनी सेना ने बाद में काफी जुल्म ढाए।

वहीं 17 मार्च 1959 को एक सैनिक के वेश में उनको भारत लाया गया। भारत में उनका दिल खोलकर स्वागत किया गया। भारत ने हमेशा तिब्बत को आजाद देश के रूप में माना और मजबूत वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंध साझा किए। वहीं 1954 में भारत ने चीन के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान इसको %चीन के तिब्बत क्षेत्र% के तौर पर स्वीकार किया। भारत आने के बाद दलाई लामा का दल कुछ समय के लिए अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में रुका। मसूरी में नेहरु से मुलाकात के बाद भारत ने 03 अप्रैल 1959 को उनको शरण दी।चीनी दमन से भाग रहे हजारों तिब्बती निर्वासितों के लिए हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला पहले से ही एक घर बन गया था। फिर दलाई दामा भी स्थायी रूप से वहां पर बस गए और निर्वासित तिब्बती सरकार की स्थापना की। हालांकि उनके इस साहसिक कदम से चीन नाराज हो गया। उन्होंने बीजिंग की ओर हाथ बढ़ाने की बार-बार कोशिश की। लेकिन उनको हर बार कम फायदा हुआ। इससे निराश होकर उन्होंने साल 1988 में घोषणा कर दी कि उन्होंने चीन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना छोड़ दिया। इसकी बजाय उन्होंने फैसला लिया कि वह चीन के भीतर सांस्कृतिक और धार्मिक स्वायत्तता की मांग करेंगे।

दलाई लामा ने साल 2011 में घोषणा की कि वह अपनी राजनीतिक भूमिका छोड़देंगे। साथ ही जिम्मेदारियों को निर्वासित तिब्बती सरकार के एक निर्वाचित नेता का सौंप देंगे। हालांकि वह अभी भी सक्रिय रहते हैं और उनके पास आगंतुकों का आना जारी है।

संपादकीय

तबाही के सबक

हालिया मानसूनी बारिश और मौसमी विक्षोभ की जुगलबंदी से हिमाचल के कई इलाकों में तबाही का जो भयावह मंजर उभरा, उसे हमें कुदरत के सबक के तौर पर देखना चाहिए। बड़ी संख्या में लोगों की मौत व लापता होने के साथ ही अरबों रुपये की निजी व सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है। निश्चय ही हाल के वर्षों में बारिश के पैटर्न में बदलाव आया है और बारिश की तीव्रता बढ़ी है। लगातार बादल फटने के बाद भयावह मंजर हमारे सामने उभरा है। निश्चय ही पूरी दुनिया में ग्लोबल वॉर्मिंग के चलते मौसम के बिगड़े तेवर नजर आ रहे हैं, लेकिन पहाड़ों में जल-प्रलय सी आपदा का मंजर निश्चय ही भयावह है। वैज्ञानिकों को इस तथ्य पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि पहाड़ों में बादल फटने की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि क्यों हुई है। इस साल की मानसूनी बारिश में मंडी जिले में बादल फटने की घटनाओं ने बुनियादी ढांचे, घरों,सड़कों और बगीचों को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया है, उसने पहाड़ों में विकास के स्वरूप को लेकर फिर नये सिरे से बहस छेड़ दी है। राज्य के तमाम महत्वपूर्ण राजमार्ग भूस्खलन और अतिवृष्टि से बाधित रहे हैं। कांगड़ा घाटी में ऐतिहासिक रेल परिवहन को स्थगित करना पड़ा है। शिमला के पास एक बहुमंजिला इमारत के भरभरा कर गिरने के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने भयभीत किया। यहां ढली इलाके में कई इमारतें गंभीर खतरे की जद में आ चुकी हैं। निश्चय ही मौसम के मिजाज में तल्खी नजर आ रही है लेकिन इस संकट के मूल में कहीं न कहीं अवैज्ञानिक विकास, खराब आपदा प्रबंधन और निर्माण में पारिस्थितिकीय ज्ञान की उपेक्षा भी निहित है। जिसने इस संकट को और अधिक बढ़ाया है। दरअसल, पानी के प्रवाह के जो प्राकृतिक रास्ते थे, हमने उन पर बहुमंजिली इमारतें खड़ी कर दी हैं। हमने अपेक्षाकृत नयी हिमालयी पर्वतमालाओं पर इतना भारी-भरकम विकास व निर्माण लाद दिया कि वे इस बोझ को सहन नहीं कर पा रही हैं।वास्तव, में हिमाचल व उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अतिवृष्टि से आपदा का जो भयावह मंजर उभर रहा है, उसके मूल में सिर्फ जलवायु परिवर्तन ही मुख्य कारक नहीं है। दरअसल, इस तबाही के मूल में हमारी नाजुक हिमालयी पारिस्थिकीय तंत्र के प्रति बड़ी लापरवाही भी है। विकास के नाम पर हमने पहाड़ों को काटकर चौड़ी सड़कें बना दी और इससे लगते पहाड़ों की जड़ें खोखली कर दी,जिससे भूस्खलन की गति अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। इस तथाकथित विकास के नाम पर हमने उन सीढ़ीनुमा रास्तों को दरकिनार कर दिया, जो पहाड़ों को मजबूती देते थे। इस तरह हमने परंपरागत हल्की छत वाले घरों के बजाय भारी-भरकम कंक्रीट की छतों वाले घरों को प्राथमिकता दी है। हिमाचल में लाहौल-स्पीति को जोड़ने वाली अटल सुरंग इंजीनियरिंग का चमत्कार हो सकती है, लेकिन इसके अवरोध के बाद पुरानी रोहतांग दर्रा सड़क पर वापसी साबित करती है कि आपातकालीन योजना ने बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ तालमेल नहीं रखा है।

वोटर सूची संशोधन संबंधी सवालों का शीघ्र हो समाधान

लेकिन लोकतंत्र में कानूनी अवयव एकमात्र पैमाने नहीं होते बल्कि नैतिक वैधता व जनता का भरोसा उतने ही मायने रखता है।चुनाव आयोग को न केवल निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए – बल्कि उसे निष्पक्षता से काम करते हुए दिखना भी चाहिए। गहराते राजनीतिक ध्रुवीकरण और संस्थानों के प्रति अविश्वास के बढ़ते माहौल के बीच सहानुभूति और स्पष्टता की कमी होने पर नेकनीयत कार्यों को भी गलत समझा जा सकता है। आयोग को दस्तावेज़ीकरण के लिए समय सीमा बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। साथ ही इसको पहले उन राज्यों में शुरू करने पर विचार करना चाहिए,

जहां चुनाव 2-3 साल बाद होने हैं।ऐसे वक्त में, संस्थान यह वास्ता देकर कि वह तो सिर्फ कानून का पालन करवा रहा है, अपनी विश्वनीयता खो सकते हैं। बाकियों की तरह, बिहार के मतदाता भी,स्वच्छ मतदाता सूची के हकदार हैं – लेकिन बड़ी संख्या में लोगों के बाहर छूट जाने की एवज पर नहीं।

बिहार में विधानसभा चुनाव होने में कुछ माह ही बचे हैं, ऐसे वक्त मतदाता सूचियों में विशेष गहन संशोधन की घोषणा से राजनीतिक दलों में आशंकाएं हैं। इस कवायद का वक्त बिहार में इसे विवादास्पद बनाता है। बेशक, इरादा चुनावी डेटाबेस अपडेट करने का है। लेकिन पुराने कागजात पेश करने में व्यावहारिक मुश्किलें हैं। ऐसे में यकीनी बने कि हरेक नागरिक का वोट देने का अधिकार सुरक्षित रहे।जब भारत के चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से ऐन कुछ महीने पहले मतदाता सूचियों में विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) किए जाने की घोषणा कर दी, तो इससे राजनीतिक हलकों में कई तरह की आशंकाएं पैदा हो गई। हालांकि चुनाव आयोग इस कवायद का बचाव संवैधानिक अनिवार्यता बताकर कर रहा है। संविधान के अनुच्छेद 326 में यह जरूरी है कि केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिक ही मतदान के हकदार हैं। आयोग के मुताबिक, वर्तमान संशोधन का उद्देश्य सूचियों में सुधार करके यह प्रावधान यकीनी बनाना है। इस विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया के तहत 2003 की मतदाता सूचियों में जिनका नाम शामिल था, उन्हें सत्यापित मतदाता माना जाएगा। अतीत में भी चुनाव आयोग उन जगहों पर गहन संशोधन करने का आदेश देता आया है, जहां उसे मतदान सूची की विश्वसनीयता संदिग्ध या पुरानी लगे।

हालांकि, जिन लोगों का नाम 2003 के बाद मतदाता सूची में शामिल हुआ है या जिन्होंने नाम कभी शामिल नहीं कराया- उन्हें अब नागरिकता की स्व-घोषणा और अन्य सहायक दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाणपत्र या माता-पिता का प्रमाणपत्र जमा कराना होगा। इसके पीछे घोषित इरादा चुनावी डेटाबेस अपडेट व शुद्ध करना है। लेकिन, ईमानदार दिखने वाली अनेक अन्य प्रक्रियाओं की तरह यहां भी छिपी चतुराई विवरण में स्पष्ट हो जाती है।

मतदाता सूचियों को संशोधित करने का विचार नया नहीं है। वास्तव में, 2003 की कवायद के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने कई पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर में बड़े पैमाने पर गहन संशोधन प्रक्रिया चलाई थी। हालांकि, तब इन संशोधनों को चुनावों से ऐन पहले नहीं करवाया गया था, न ही चुनिंदा मतदाता समूहों के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़ों की आवश्यकता थी। इससे पहले भी, बिहार सहित 20 अन्य राज्यों में चरणबद्ध तरीके से इसी किस्म की कवायद हुई थी। एसआईआर मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया का आधारभूत अवयव हैं – विशेषतया बड़े पैमाने पर हुई कवायदों में जैसे परिसीमन, किसी क्षेत्र में उथल-पुथल उपरांत शांतिकाल या डिजिटलीकरण।2003 व 2004 के बाद से वार्षिक सारांश संशोधन सामान्य प्रक्रिया बन गये। साल 2004 के बाद किसी भी राज्य को चुनाव आयोग के सचेत निर्णय चालित गहन संशोधन नहीं करना पड़ा, क्योंकि घर-घर सर्वेक्षण के अलावा वार्षिक सारांश रिपोर्ट पर्याप्त थी। स्थापित प्रथा से विचलन व जिस वक्त यह कवायद की जा रही है, वह बिहार में इसे विवादास्पद बनाता है।

निस्संदेह, मतदाता सूचियों को नियमित अपडेट किया जाना चाहिए – लेकिन बिहार जैसे बाढ़-ग्रस्त, उच्च-प्रवासन वाले राज्य में मतदान से बमुश्किल चार महीने पहले ऐसा करना इसे बहुत मुश्किल काम बनाता है। चिंता वैधता की नहीं; बल्कि व्यावहारिकता व कार्यान्वयन से उपजने वाली राजनीतिक दृश्यावली को लेकर है।मूलतः, यह संशोधन प्रमाण पेश करने का भार मतदाता पर डाल रहा है। जिन लोगों के नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं हैं, उन्हें अब दस्तावेज़ी साक्ष्यों के साथ अपनी प्रमाणिकता साबित करनी होगी। सैद्धांतिक रूप में भले यह उचित लगता हो, किंतु व्यावहारिक पटल पर इससे उन लोगों को मताधिकार से वंचित करने का खतरा बन जाता है, जिनकी सरकारी कागजात पूरा करने की दरकारों में फंसने की गुंजाइश सबसे अधिक है, मसलन, प्रवासी मज़दूर, दलित, आदिवासी, शहरी ग़रीब, अल्पसंख्यक, बुज़ुर्ग और महिलाएं- जिनमें से अधिकांश के पास जन्मप्रमाण पत्र या माता-पिता के दस्तावेज़ नहीं। ऐसे लोगों के लिए उनका नाम पिछली मतदाता सूची में होना पर्याप्त माना जाना चाहिए था, खासकर अब जबकि डिजिटलीकरण काफी उन्नत है। यहां पर असम की एनआरसी प्रक्रिया के साथ समानता करने से बच नहीं सकते। वहां भी, ऐतिहासिक दस्तावेज़ों की अनिवार्यता पूरी न किए जाने के कारण लगभग बीस लाख लोग मतदान सूची से बाहर हो चुके हैं, जिनमें से अधिकतर ग़रीब हैं। जबकि चुनाव आयोग का दावा है कि एसआईआर चुनावी प्रक्रिया है-न कि नागरिकता की पड़ताल।इस मुद्दे को और जटिल बनाता है,व्यापक परामर्श का अभाव। विपक्षी दलों का आरोप है कि विशेष गहन संशोधन को बिना किसी पूर्व सूचना के या उनसे चर्चा किए बिना शुरू कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने 2002-03 में 20 राज्यों में एसआईआर और पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर में 2004 के संशोधन करने के दौरान, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के साथ पहले मशविरा किया था। ऐसी कवायद जल्दबाजी में नहीं बल्कि अक्सर चुनावों से कई साल पहले की जाती थी, जिससे फीडबैक, जन जागरूकता मुहिम और पार्टियों की भागीदारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

विगत में चुनाव आयोग ने 2003 की मतदाता सूची को ऑनलाइन प्रकाशित किया और घर-घर जाकर सत्यापन में मदद करने के लिए करीब एक लाख बूथ-स्तरीय अधिकारियों और इतने ही वालंटियर तैनात किये। सबसे महत्वपूर्ण यह कि इसने स्पष्ट किया है कि 2003 की सूचियों में पहले से शामिल 4.96 करोड़ मतदाताओं को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं। वर्तमान में भले ही चुनाव आयोग ने दावों-आपत्तियों की प्रक्रिया खोल दी व राजनीतिक दलों से बूथ स्तर पर एजेंट नियुक्त करने को भी कहा है। ये सभी कदम स्वागत योग्य हैं, लेकिन संशोधन प्रक्रिया की चिंताओं का निवारण करने में पर्याप्त नहीं।

बेशक विशेष गहन संशोधन का कानूनी आधार मजबूत है। अनुच्छेद 324 ,अनुच्छेद 326, मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 का नियम 25 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21, मतदान सूचियों को वक्त मुताबिक संशोधित करने का समर्थन करती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने भी इन मामलों में आयोग की स्वायत्तता की पुष्टि की है।

बड़े लक्ष्यों के लिए बहुत कुछ करना बाकी

हिमाचल प्रदेश ने देश की शिक्षा व्यवस्था में एक नया अध्याय लिखा है, जो न केवल राज्य की उपलब्धि है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। हिमाचल ने वर्ष 2021 के नेशनल अचीवमेंट सर्वे में 21वें स्थान से छलांग लगाकर 2025 में 5वां स्थान प्राप्त किया है। यह बदलाव मात्र आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि उस नीति परिवर्तन का प्रमाण है, जिसे प्रदेश में व्यावहारिक रूप में लागू किया गया है। शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय को ठोस कार्रवाई से जोड़कर एक अनुकरणीय मॉडल बना दिया गया है। इस मॉडल का आधार शिक्षण गुणवत्ता में सुधार, प्रशासनिक दक्षता और प्रमाण-आधारित नीति निर्माण रहा है।राज्यों की शिक्षा व्यवस्था की रैंकिंग के पीछे कई कारण होते हैं। पंजाब और हरियाणा में बेहतर छात्र-शिक्षक अनुपात, मजबूत स्कूल प्रशासन और सामुदायिक भागीदारी ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक ने प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण और विकेन्द्रित शैक्षणिक योजना का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। दूसरी ओर, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य शिक्षकों की अनुपस्थिति, उच्च छात्र-शिक्षक अनुपात और कमजोर बुनियादी ढांचे की समस्याओं से जूझ रहे हैं। दिल्ली में प्रशासनिक टकराव और प्रवासन के कारण सरकारी स्कूलों में अत्यधिक नामांकन से शिक्षा की गुणवत्ता में विसंगति बनी रहती है। जम्मू-कश्मीर में मौसम और सुरक्षा संबंधी बाधाओं के कारण लॉजिस्टिक समस्याएं बनी रहती हैं। इस प्रकार, प्रशासनिक क्षमता और प्रणालीगत असमानताएं राज्यों की शिक्षा रैंकिंग को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

हिमाचल की बात करें तो 2000 के दशक में इसकी शुरुआत एक मजबूत नींव के साथ हुई थी, लेकिन 2017 तक ठहराव आ गया और फिर कोविड-19 महामारी के बाद 2021 में भारी गिरावट दर्ज की गई। लेकिन वर्ष 2025 में शिक्षा के बुनियादी स्तर पर केंद्रित सुधार,

प्रशासनिक पुनर्गठन और प्रमाण-आधारित फैसलों ने एक नई ऊर्जा भर दी। सरकार ने 1,160 गैर-कार्यशील स्कूलों को बंद करने का साहसिक निर्णय लिया, जिनमें 911 प्राथमिक, 220 मिडल, 14 हाई और 15 सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल थे। इनमें अधिकतर स्कूलों में छात्र संख्या नाममात्र थी या वे संचालन के मानकों का उल्लंघन कर रहे थे। सरकारें इस विषय पर स्थानीय विधायकों और वोट बैंक के दबाव में झुकती रहीं, लेकिन अब शासन ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य के सीमित संसाधनों को केवल जनहित में प्रभावी उपयोग में लाया जाएगा।हिमाचल की एनएएस रैंकिंग में सुधार के पीछे छह ठोस नीतिगत बदलाव रहे। राज्य ने एक हजार से अधिक कम नामांकन वाले स्कूलों का विलय कर शिक्षक नियुक्तियों को व्यावहारिक बनाया और प्रशासनिक खर्च घटाया। शिक्षा निदेशालय को पूर्व-प्राथमिक से लेकर 12वीं कक्षा तक एकीकृत कर दिया गया जबकि उच्च शिक्षा को अलग कर दिया गया, जिससे जवाबदेही और निगरानी को स्पष्ट दिशा मिली। राज्य ने अंग्रेज़ी को कक्षा-1 से माध्यम बनाकर भाषा सीखने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। यूनिफॉर्म को लेकर छात्रों में भागीदारी और पहचान की भावना को बल दिया गया। साथ ही, योग्य छात्रों और शिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव दिलाने के लिए विदेश भेजा गया। जिससे वैश्विक दृष्टिकोण और नवाचार कक्षा में प्रवेश पा सके। स्कूलों को शैक्षणिक क्लस्टर में बांटकर संसाधनों का साझा उपयोग, सहयोगात्मक शिक्षण और निगरानी की प्रणाली सशक्त हुई।एनएएस 2025 के आंकड़े इस प्रभावी बदलाव को सिद्ध करते हैं। कक्षा-3 के छात्रों ने एनआईपीयूएन भारत मिशन के तहत उल्लेखनीय प्रगति की है। सरकारी स्कूलों ने कई निजी स्कूलों को पीछे छोड़ दिया और ग्रामीण एवं बालिका वर्ग ने राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है।हालांकि, चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। केवल 26 प्रतिशत शिक्षकों ने निरंतर पेशेवर विकास कार्यक्रम में भाग लिया है। दिव्यांग छात्रों के लिए केवल 30 प्रतिशत स्कूलों में अनुकूल ढांचा उपलब्ध है और 35 प्रतिशत में ही प्रशिक्षित शिक्षक हैं। व्यावसायिक शिक्षा को लेकर छात्रों में रुचि की कमी भी देखी गई है—45 प्रतिशत स्कूलों में उपलब्धता के बावजूद केवल 41 प्रतिशत छात्र ही कौशल पाठ्यक्रमों का चयन कर रहे हैं।बहरहाल, अभी भी राज्य को कुछ अहम रणनीतियों पर अमल करना होगा। निपुणता आधारित शिक्षा को संस्थागत बनाना, एनएएस डेटा को स्कूल सुधार योजनाओं से जोड़ना, शिक्षक प्रशिक्षण को डेटा-आधारित और सतत बनाना, सीपीडी को केवल औपचारिकता से निकालकर वास्तविक परिवर्तन का माध्यम बनाना, और व्यावसायिक शिक्षा को उद्योगों से जोड़कर प्रासंगिक बनाना आवश्यक होगा।पिछले 25 वर्षों में एनएएस ने शिक्षा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 2025 का संस्करण दक्षता, समानता और नीति संगत है। इस यात्रा में हिमाचल प्रदेश की भागीदारी लगातार मजबूत हुई है, जिससे वह राष्ट्रीय शिक्षा विमर्श का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है।

कलिकाल में वर्षा ऋतु वर्णन के बदलते मायने

पुराने समय में लोग आदर्शवादी नैतिकतावादी होते थे, इसलिए कवि शायर भी वैसी ही बातें करते थे। अब समय तेजी से बदल रहा है। पिछले मानदंड ध्वस्त हो रहे हैं। नए-नए कीर्तिमान बन रहे हैं। साहित्य में भी अज्ञेय के प्रयोगवाद से नए उपमान नए प्रतीक नए बिम्ब सामने आ रहे हैं। रामचरित मानस में भी महाकवि तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। कलिकाल है अत: ऋतु वर्णन में भी युगानुरूप नवीनता होनी चाहिये। है कि नहीं ?

हम रविवार को संध्याकाल में घर की छत पर ऋतुफल के साथ वर्षा ऋतु का उचित विधि से आनंद उठा रहे थे। मैंने अपने साथी को वास्तविक मित्र मानते हुए कहा, देखो आकाश में काले बादल ऐसे घिर आये हैं जैसे चुनावों के समय बड़े राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर दूरदराज के नेताओं की भीड़। इन्हें देखकर लगता है किसी नेता के मंत्री पद की शपथ लेते ही उसके समर्थकों बंधु-बांधवों ने उसे घेर लिया हो। इन काले बादलों को देखकर मोर नृत्य कर रहे हैं मानो सरकारी दफ्तर में सप्लायर के आते ही सभी लिपिक लेखापाल के साथ झूमने लगे हों। ये बादल घुमड़-घुमड़कर गर्जना कर रहे हैं, मानो सत्तारूढ़ नेता अपने कार्यकाल में प्रजा की खुशहाली की घोषणा कर रहा हो। बिजली क्षण भर कौंधकर लुप्त हो जाती है मानो वोटर की उम्मीद हो। देखो कैसी मूसलाधार बारिश हो रही है जैसे पुल निर्माण के समय लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन मंत्री के यहां स्वर्ण मुद्रायें गिरती हैं।गौर से देखो मित्र! नदी-नाले किनारों की मर्यादा भंग कर बह रहे हैं लगता है नवधनाढ्य अपने शहर की गलियों में इतरा कर चल रहा है। वर्षा का जल सभी ओर से आकर जलाशयों में एकत्र हो रहा है जैसे हमारे यहां कालाबाजारियों और बड़े उद्योगपतियों के यहां धन इकट्ठा होता है। चारों ओर की धरती हरी हो गई है जैसे किसी नेत्र चिकित्सक ने जांच कक्ष में चहुं ओर हरे परदे लगा लिये हों। सभी दिशाओं में मेढकों की ध्वनि गूंज रही है जैसे चुनाव की घोषणा होते ही विपक्षी नेताओं के स्वर गूंजने लगते हैं।

अब नेता जी को ऐसा क्या कीड़ा काटा

पंकज सीबी मिश्रा /राजनीतिक विशलेषक एवं पत्रकार जौनपुर यूपी

लोकतंत्र का खेल पहले वोट पर चलता था और अब जाति पर चलता है। बात ताज़ा राजनीति पर तो 2027 से पहले भाजपा के सॉलिड वोट को चट करने की विपक्ष ने तमाम रणनीति बनाई। जैसे करनी सेना बनाम ब्राह्मण -यादव किया, राजपूत वोट को हिट किया। काफ़ी सफलता भी मिली, पर दिक्क़त ये कि 2027 में ये नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ का चेहरा सामने होगा तो राजपूत वोट खुद ब खुद एकजुट हो पड़ेगा। सो जो ठाकुर साब लोग जय समाजवाद किये थे वो जल्द ही पार्टी के पत्र द्वारा दुत्कार दिए गए। अब नेता जी नें जाल डाला दलित वोट पर और पीडीए कह कर उन्हें लुभाने के लिए सवर्ण समाज की बलि दी गई। ख़ास कर जाटव पर मेहरबान हुए और उन्हें फ़साने को जाल फेंका गया। अब वहाँ भी दिक्क़त जाटव वोट अभी चार हिस्से में है, एक बड़ा हिस्सा मायावती के पास, एक हिस्सा रावण के पास एक हिस्सा भाजपा के पास सो बड़ा छोटा भाग हाथ लगेगा। अब लखनऊ की गद्दी पाना हो तो आपको एक बड़ा जातिय वोट बैंक तो और चाहिए यादव मुस्लिम के अलावा। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बड़े लम्बे समय से सत्ता पलटने वाला वोट रहा है। ये ब्राह्मण ही थे जो सतीशचंद्र मिश्रा के बहकावे में आकर मायावती की बहुमत की सरकार बनवायी, और मनोज पाण्डेय, पवन पाण्डेय जैसो के कुचक्र में फंस कर अखिलेश को बहुमत देने में बड़ी भूमिका निभाई थी, वर्तमान भाजपा सरकार से अब तक ब्राह्मण वोट जुड़ा हुआ है। ऐसे में अखिलेश बेचैन है, अब नेता जी को ऐसा क्या कीड़ा काटा जो यादव बनाम ब्राह्मण की राजनीति करने उतर पड़े ! जबकि पूर्वांचल में 2027 में उन्हें काफ़ी फायदा भी दे सकता था ये वोट। अच्छा यादव वोट को भी ध्रुवीकृत करने की दरकार नहीं।काहे के मुलायम को जहाँ जीवन में कभी 66-67त्न से ऊपर यादव वोट न मिला अखिलेश को 2022 और 2024 के चुनाव में 85त्न तक यादव वोट मिला है भईया इससे आगे कोई उम्मीद दिखती नहीं। तो यादव वोट बढ़ने का भी फायदा नहीं, ब्राह्मण वोट जो मिल सकता था उसे भी खुद मना करना है तो अखिलेश चाहते क्या हैं आखिर ? क्या ये मूर्खता कर डाली उन्होंने ! नहीं !बेहद कैलकुलेटेड राजनीतिक चाल है। अखिलेश यादवों को भावनात्मक मुद्दों में उलझा रहे हैं। अभी ऐसे और भी कांड करतूत होंगे बात का बतंगड़ बनेगा और इसका फायदा क्या होगा ? इसका फायदा अखिलेश 2027 में टिकट वितरण में जातिय गणित बैठा लेंगे। लोकसभा की ही तर्ज़ पर यादवों को या तो टिकट मिलेंगे नही या बेहद कम क्यूंकि ये प्रयोग सफल रहा था। यानी यादव वोट तो सपा को दे, कंडीडेट अन्य जाति से हो जिससे कैंडिडेट का सजातीय वोट जुड़ जीत का फार्मूला बने । 120+ सीट ऐसी हैं जहाँ यादव टिकट के दावेदार होते हैं सीधे। मेरा अनुमान है अखिलेश 20 टिकट भी नहीं देने वाले। उनमें भी कुनबे वाले और रिश्तेदार होंगे ज्यादातर या गगन यादव जैसे नमूने। इटावा में जो कुछ भी हुआ उसका शुरू से लेकर अब तक कोई समर्थन नहीं करता मै किन्तु एक जाति को दूसरे जाति के खिलाफ खड़ा करने वालों को बख्शा भी नहीं जाना चाहिए।कुछ साथियों नें मेरा मत जानना चाहा इटावा कांड के बारे में तो बता दूँ चोटी काटना, सर मुंडवाना गलत है क़ानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। चार सौ बीस लोगो को पकड़ पुलिस में रिपोर्ट करते, जो कि बाद में गिरफ्तारी भी हुई। उसके बाद अब जो हो रहा है वो भी सर्वथा गलत है क्यूंकि कुछ गुंडे नेता बनने के चक्कर में यादवों को ब्राह्मणो से लड़वाने के मंसूबे से इटावा में घुसे, पुलिस तक पर हमला किए। यह कल की घटना एक साजिश है। हजारों की संख्या में गांव पर चढ़ाई करना ये क़ानून को चुनौती है। सरासर गुंडागर्दी है। अरे संवैधानिक रूप से अपना पक्ष कोर्ट में रखें। वेवजह राजनीति का शिकार होकर मामले को ब्राह्मण बनाम यादव बनाकर राजनीतिक गोटियां सेंकने से क्या होगा ? एक पार्टी के हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेराआपसे यही कहना है कि आप तो ब्राह्मणों को जोड़ने की बातें विगत दिनों से कर रहे हैं फिर जो कल लोग दादागिरी पर उतरे उनका विरोध किया क्या आपने ? कभी कभी होता ये है कि ' न खुदा ही मिला न बिसाले सनम न इधर के रहे न उधर के रहे'। नेता जी सनातन कि जाति तोड़ने पर हम फिर गुलाम होंगे आपके इस करतूत से। वैसे भी चन्द लोगों के दोष को आप पूरे समाज पर नहीं मढ़ सकते। मेरी दृष्टि में अब कानून को अपना काम करने देना चाहिए वेवजह मामले को तूल देना गलत है। अब भारत जैसे देश में आप काम और वादों पर वोट नहीं ले सकते ।वजह वोटर लालची तो नेता झूंठे सो साहब तरीक़ा राजनेता अपनाते हैं भावनात्मक मुद्दों को आगे कर ध्रुविकरण करने का वोटों के। सारे राजनितिक दल ये प्रयोग सत्ता के चक्कर में किये। कामयाब रहें।

जापान में एक बच्चे के लिए वहां की सरकार ट्रेन चला सकती है लेकिन यूपी सरकार 50 बच्चों के लिए स्कूल नहीं चला सकती।

अपनी समस्या हमें बतायें

आपके साथ या आपके आस-पास कोई घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, जुर्म हुआ है या उत्पीड़न हुआ है अथवा आपके क्षेत्र की समस्या है और आपकी समस्या जायज है तो आपकी समस्याओं के समाधान हेतु सम्बन्धित उच्च अधिकारियों एवं शासन-प्रशासन तक पहुंचाने के लिये बी पी एस न्यूज आपके साथ है। आपकी खबर शत् प्रतिशत प्रकाशित की जायेगी। एवं आपका नाम व नम्बर आपके अनुसार प्रकाशित या पूर्णतया गुप्त रखा जायेगा।

दिये गये नम्बर पर काल करें या हमें ई मेल करें।

फोन नं.- 8423454502, bps.knp786@gmail.com

आवश्यक सूचना

प्रिय ग्राहकों/विज्ञापनदाताओं को सूचित किया जाता है कि बी.पी.एस. न्यूज समाचार पत्र में नगद भुगतान की व्यवस्था नहीं है। कृपया चेक/डी.डी. बी पी एस न्यूज के नाम से ही चेक आदि भेजें। नगद भुगतान की व्यवस्था नहीं है। नगद भुगतान करने पर विज्ञापनदाता स्वयं जिम्मेदार होंगे। - संपादक

आवश्यकता है

बी पी एस न्यूज राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक, साप्ताहिक समाचार पत्र व ऑनलाइन न्यूज चैनल (पोर्टल) के लिये समस्त तहसीलों एवं ब्लाक स्तर पर ब्यूरो चीफ, संवाददाताओं, छायाकार तथा विज्ञापन प्रतिनिधियों युवक-युवतियों की आवश्यकता है।

संपर्क करें -:

मो.: 8423454502

email:bps.knp786@gmail.com

ट्रैक्टर चालक की हत्या- पुलिस तेजी दिखाती तो बच सकती थी जान, परिजनों ने पुलिस को दे दी थी अपहरण की सूचना

बीपीएस न्यूज

कानपुर। पुलिस के अनुसार इरफान ने भाइयों व आधा दर्जन लोगों के साथ मिलकर बुधवार रात नौ बजे विमल का मौरंग मंडी से अपहरण कर लिया। नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपी अपहरण के बाद विमल को सफेद कार से ले जाते कैद हो गए।

कानपुर में सेन पश्चिम पारा पुलिस तेजी दिखाती, तो ट्रैक्टर चालक विमल गौतम की जान बच सकती थी। बुधवार की रात करीब साढ़े नौ बजे अपहरण की घटना होने के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दे दी थी, लेकिन रिपोर्ट अगले दिन दर्ज हुई। घरवालों का आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा है कि उनकी हत्या कर दी गई। डीसीपी दीनेंद्र नाथ

चौधरी ने कहा कि पुलिस की कोई लापरवाही नहीं है। सूचना के बाद से ही टीमें चालक की तलाश में जुट गई थीं।पुलिस ने मुख्य हत्यारोपी इरफान को इटावा से उठा लिया है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं दिखाई है। उसकी सफेद कार भी इटावा से मिली है। वहीं, थाना प्रभारी कहना है कि कार इरफान के रमईपुर स्थित घर से मिली है। पूछताछ चल रही

है।जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर आशुतोष कुमार सेन पश्चिम पारा थाने पहुंचे। मृतक की पत्नी विटान जेसीपी की गाड़ी के सामने खड़ी होकर न्याय की गुहार लगाते हुए हत्यारोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करती रही। एडीसीपी, एसीपी और थाना प्रभारी ने उनको समझाबुझा कर शांत कराया।

एक सप्ताह से बिनगवां में दिख रहा था इरफान

पुलिस की जांच में सामने आया कि खागल पासवान और विमल से विवाद के बाद इरफान बिनगवां गांव छोड़कर रमईपुर में शटरिंग का काम करने लगा। बिनगवां में शटरिंग का काम मिलने से वह पिछले एक सप्ताह से गांव में नजर आ रहा था। विमल के बेटे दिव्यांशु ने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर इरफान पिता की रेकी कर रहा था। हत्याकांड में गांव के अन्य लोग भी शामिल हैं।

गवाह की अपहरण के बाद हत्या का मुख्य आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार

कानपुर। सेन पश्चिम पारा पुलिस ने गवाह की अपहरण के बाद हत्या करने के मुख्य आरोपी इरफान और उसके साथी रोहित को शुक्रवार देर रात मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। दोनों बाइक से कानपुर देहात की ओर जा रहे थे। मुठभेड़ में गोली इरफान के पैर में लग गई। उसे प्राथमिक उपचार के लिए हैलट अस्पताल ले जाया गया। दोनों से पूछताछ के बाद तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार हुई, जबकि एक फरार है।

बिनगवां गांव निवासी ट्रैक्टर चालक विमल गौतम (49) पांच साल पुराने हत्या के प्रयास और एससी-एसटी एक्ट के मामले में गवाह थे। उनका बुधवार देर रात अपहरण कर लिया गया। परिजनों ने पड़ोसी इरफान ओर साथियों के पर अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई

थी। शुक्रवार सुबह विमल का शव डांडेपुरवा गांव के पास पनकी नहर किनारे मिला था। अपहरण की घटना सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में आ गई थी। सेन पश्चिम पारा पुलिस इरफान ओर उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी थी। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि देर रात पुलिस को सूचना मिली। रमईपुर-सचेंडी मार्ग पर गढ़ेवा मोहसिनपुर गांव के पास घेराबंदी की गई। इस दौरान इरफान और उसका साथी कानपुर देहात के रोहित उर्फ बबलू बाइक से जाते हुए दिखे। पुलिस के रोकने पर इरफान ने फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इरफान के पैर में गोली लग गई। उसे और रोहित को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से तमंचा और दो कारतूस मिले। शनिवार की सुबह बिनगवां निवासी करन वर्मा, राजा और आलोक को भी गिरफ्तार कर लिया। कानपुर देहात के अंकित की तलाश चल रही है। अब तक पांच आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सेन पश्चिम पारा थाना प्रभारी कुशलपाल सिंह ने बताया कि अपहरण के बाद आरोपी विमल गौतम को पनकी नहर के पास ले गए थे। वहां अंगौछे से उसका गला कसा गया फिर सिर पर डंडे से हमलाकर मौत के घाट उतार दिया।हत्या के बाद से ग्रामीणों में नाराजगी थी। यहां का माहौल न खराब हो उसके लिए अधिकारियों ने विमल के घर पर क्षेत्रीय पुलिस के साथ एक कंपनी पीएसी तैनात की थी। पोस्टमार्टम के बाद शनिवार को परिजनों ने नजफगढ़ घाट में विमल का अंतिम संस्कार कर दिया।

आसरा आवास योजना, घाटमपुर के निर्माण कार्य का डीएम ने किया निरीक्षण

परियोजना में अनावश्यक विलंब पर लगाई फटकार, सीडीओ को सौंपी जांच

बीपीएस न्यूज

कानपुर,जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा आज घाटमपुर स्थित आसरा आवास योजना के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया।784 भवनों का स्ट्रक्चर तैयार होने के बावजूद किसी भी आवंटी को अब तक आवास न मिलने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और इस परियोजना के क्रियान्वयन में हुई अनावश्यक देरी की जांच मुख्य विकास अधिकारी को सौंपने के निर्देश दिए।कार्यदायी संस्था सीएनडीएस द्वारा वर्ष 2013 में शहरी गरीबों के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत कुल 840 आवास, ओवरहेड टैंक, बोरिंग व पंप हाउस, जलापूर्ति व सीवर लाइन जैसे कार्य प्रस्तावित थे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी को बताया गया कि अब तक लगभग 35 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, फिर भी योजना का कोई प्रत्यक्ष लाभ लाभार्थियों तक नहीं पहुँच सका है। इस पर जिलाधिकारी ने जिम्मेदार अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।परियोजना प्रबंधक सर्वेश कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि वर्ष 2019 से निर्माण कार्य रुका हुआ है और अब केवल सैनिटरी तथा विद्युत फिटिंग जैसे कार्य शेष हैं, जिनके लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।

यह भी अवगत कराया गया कि सितम्बर 2024 में 784 आवासों के सापेक्ष लॉटरी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। डीएम ने परियोजना में विलंब के संबन्ध में अधिशासी अधिकारी घाटमपुर नगर पालिका की जवाबदेही एवं जिम्मेदारी तय करने के संबन्ध में आरोपपत्र देने के भी निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जुलाई माह के अंत तक सुरक्षा उपायों के साथ पात्र लाभार्थियों को आवास आवंटित कर शिफ्ट कराया जाए।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी और समयबद्ध कार्यवाही न होने के कारण शहरी गरीब अब तक इस योजना से वंचित हैं। परियोजना से संबंधित शेष बचे कार्यों को पूर्ण कराने हेतु नगर पालिका घाटमपुर को निर्देशित किया गया है कि वे अपने संसाधनों अथवा सूडा/डूडा से आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कर अविलंब कार्य पूर्ण कराएं, जिससे लाभार्थियों को शीघ्र आवास मिल सके।जिलाधिकारी ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगभग दस वर्षों के बाद भी यह परियोजना अधूरी पड़ी है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि अब किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस देरी के लिए उत्तरदायी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डॉ.महादेव को कानपुर महानगर कांग्रेस कमेटी का सचिव नियुक्त किया गया

बीपीएस न्यूज

कानपुर,डॉ. महादेव को कानपुर महानगर कांग्रेस कमेटी का सचिव नियुक्त किया गया है उनके द्वारा कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया गया । डॉश महादेव को कांग्रेस पार्टी का जिला सचिव बनाए जाने पर शिक्षक समुदाय द्वारा अपार हर्ष व्यक्त किया गया एवं उनका अभिनंदन किया गया। डॉश महादेव एक विख्यात शिक्षाविद् एवं जीवन विज्ञानी हैं और कई सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं वह एम 0एल 0सी0 का चुनाव भी लड़ चुके है तथा उनके पास जिले में पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद पर कार्य करने का सांगठनिक अनुभव भी है। समय समय पर शिक्षकों की समस्याओं के समाधान की लड़ाई जिले और प्रदेश स्तर पर लड़ते रहते हैं। कई बार भूख हड़ताल पर भी बैठ चुके हैं। डॉ0 महादेव ने कार्य भार ग्रहण करने के बाद कहा कि वह शोषितों पीड़ितों एवं वंचितों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस की विचारधारा एवं मानवतावादी सिद्धांतों के अनुरूप पार्टी कार्य निष्ठा पूर्वक करेंगे । उन्होंने कहा कि देश की सांप्रदायिक जातिवादी ताकतों को हराने एवं सामाजिक समरसता व भाईचारा बनाए रखने व संविधान विरोधी ताकतों से संविधान को बचाने के लिए आज देश को कांग्रेस पार्टी की जरूरत है।

अवैध शराब बनाने के लिए लाई गई 740 लीटर स्प्रिट बरामद, गोदाम संचालक गिरफ्तार

कानपुर। बिहार में अवैध शराब की सप्लाई के लिए शहर लाई गई 740 लीटर स्प्रिट को बाबूपुरवा पुलिस ने बुधवार को टीपीनगर स्थित गोदाम में छापा मारकर जब्त किया। बाबूपुरवा इंस्पेक्टर अरुण कुमार द्विवेदी ने बताया कि स्प्रिट की गंध की शिकायत मिलने पर आबकारी विभाग के निरीक्षक फरजन्द अली की टीम के साथ दबिश दी गई। वहां 37 गत्तों में रखी स्प्रिट रखी मिली। टीम ने मिर्जापुर जिले के बभनी गांव निवासी गोदाम संचालक चन्द्रप्रकाश दुबे को गिरफ्तार किया। उसने बताया कि माल लखनऊ होते हुए बिहार जाना था। माल की डिलीवरी बिहार के गोपालगंज जिले में होनी थी। लीकेज होने के चलते ट्रांसपोर्टर ने माल ले जाने से इन्कार कर दिया था।

जानलेवा जाम तीसरी मंजिल से अलमारी उतार रहा परिवार करंट की चपेट में आया, किशोरी की मौत, मां गंभीर

कानपुर। बर्रा आठ में गुरुवार की शाम को घर में उतर आए करंट की चपेट में आकर दस वर्षीय किशोरी की मौत हो गई, जबकि उसके माता, पिता और सात साल का भाई झुलस गए। सभी का उर्सला अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह हादसा घर के बगल से गुजरी एचटी लाइन के छज्जे से छूने की वजह से हुआ, जिससे तीसरी मंजिल की रेलिंग, गैलरी, जीने, दीवार पर करंट फैल गया। चारों लोग मकान शिफ्ट करने के दौरान लोहे की अलमारी उतारने की तैयारी कर रहे थे। क्षेत्रवासियों ने केस्को के खिलाफ नाराजगी जताई।

घाटमपुर के अमित सविता पिछले कुछ वर्षों से परिवार समेत बर्रा आठ में राजन कुश्वाहा के मकान की तीसरी मंजिल में किराये पर रह रहे थे। वह नजदीक ही सैलून चलाते हैं। उन्होंने दूसरी जगह घर ले लिया है। गुरुवार को सामान शिफ्ट कर रहे थे। बताया जा रहा है कि चारों लोहे की अलमारी जीने के रास्ते से नीचे उतारने की तैयारी कर थे।

अचानक करंट आ गया, जिसकी चपेट में आकर अमित, उनकी पत्नी अनामिका सविता, दस साल की बेटी काव्या और सात वर्षीय बेटा अंश झुलस गए। उनकी चीख पुकार सुनकर अन्य किरायेदार और पड़ोसी बाहर निकल आए। लाइन बंद कराकर सभी को निजी अस्पताल ले जाया गया। गुजैनी पुलिस भी आ गई। चारों को हैलट ले जाया गया, जहां बर्न वार्ड की सुविधा न होने पर डॉक्टरों ने उर्सला भेज दिया।

किशोरी ने उर्सला अस्पताल में दम तोड़ दिया। किरायेदारों ने पुलिस से बताया कि एचटी लाइन तीसरी मंजिल के छज्जे के बिल्कुल बगल से गई है। यहां बांस का टुकड़ा लगाकर तार को दूर कर दिया गया था। सवेरे हवा चलने से बांस के टुकड़े के गिरने की आशंका है, जिससे लाइन छज्जे से छू गई।

अचानक दीवार, फर्श और रेलिंग में करंट फैल गया। डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि करंट से झुलसकर किशोरी की मौत हो गई है, जबकि महिला की हालत गंभीर है। केस्को के अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है।

सामान शिफ्ट करने से पहले शटडाउन के लिए सब स्टेशन में आवेदन करना चाहिए था। केस्को के कर्मचारी अपनी देखरेख में पूरा कार्य करवाते, जिससे कोई हादसा नहीं होता। हादसे के संबंध में जेई से जानकारी कराई जा रही है।-सैमुअल पॉल एन, एमडी केस्को

उद्योगों की आवश्यकतानुसार तैयार हो आईटीआई का पाठ्यक्रम

बीपीएस न्यूज

कानपुर। आईटीआई एडवाइजरी काउंसिल की बैठक बुधवार को आईटीआई परिसर में उद्योग संगठन के पदाधिकारियों के साथ हुई। इसमें आईटीआई संस्थान में प्रशिक्षण ले रहे युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, प्रशिक्षण का स्तर बेहतर करने समेत कई बिंदु पर चर्चा की गई। कहा गया कि उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप आईटीआई का पाठ्यक्रम तैयार किया जाए।

बैठक में फीटा के महासचिव उमंग अग्रवाल, अब्दुल अली, लघु उद्योग भारती के लाडली प्रसाद, आईआईए से दिनेश बरसिया, पीआईए से मनोज बंका ने सुझाव दिए। बैठक में उद्योग एवं आईटीआई की समन्वय समिति का गठन किया गया।

निर्णय लिया गया कि स्थानीय उद्योग प्रतिनिधियों के साथ एक स्थायी इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा, जो पाठ्यक्रम, इंटर्नशिप, उपकरण और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण में मार्गदर्शन और सहयोग करेंगे। यह भी तय हुआ कि उद्योगों की वर्तमान आवश्यकताओं को समझकर ही पाठ्यक्रम का अध्ययन कराया जाएगा।

नई तकनीक जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आईटी, सीएनसी मशीनिंग, डेटा विश्लेषण आदि को उद्योग प्रतिनिधियों के सहयोग से पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

उद्योगों के सहयोग से अनिवार्य ऑन द जॉब ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम संचालित होंगे। सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ युवाओं को देने की बात कही गई। आईटीआई के प्रशिक्षकों को उद्योगों में प्रशिक्षण देने का भी निर्णय किया गया। फीटा के अब्दुल अली ने कहा कि वो 20 छात्रों को कंप्यूटर अपग्रेडेशन का कोर्स अपने संस्थान में कराएंगे। छात्रों ने कोर्स की शर्तें पूरी की तो उन्हें अपने यहां रोजगार भी देंगे। सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार मेले लगाए जाएं।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, एचबीटीयू, आईआईटी एवं उद्योगों के साथ मिलकर पाठ्यक्रम को आधुनिक एवं नवीनतम स्तर पर तैयार किया जाए। बेहतर सामंजस्य के लिए सभी आईटीआई संस्थानों के साथ उद्योगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए। हर तीन महीने में एडवाइजरी काउंसिल की बैठक नियमित रूप से हो।

इनोवेशन और इनक्यूबेशन हब भी आईटीआई में बनाने का सुझाव दिया गया। उपनिदेशक ने बताया कि उद्योग जगत छात्रों को अपनी जरूरत के मुताबिक कोर्स करा सकते हैं। और कोर्स में स्वयं बदलाव भी कर सकते हैं। इसके लिए आईटीआई प्रति छात्र उद्योगों को भुगतान भी करेगा। बैठक में संयुक्त निदेशक आरके मौर्य, नोडल प्रधानाचार्य हरीश कुमार मिश्रा, विवेक शुक्ल, विशाल नड्डा, बद्री प्रसाद दीक्षित आदि थे।

पेंशनरों ने उठाई मांग, कहा- बढ़ाई जाए पेंशन, पति-पत्नी को मिले निशुल्क इलाज

कानपुर। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश की प्रांतीय बैठक बुधवार को रावतपुर के सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप यूनियन कार्यालय में हुई। इसमें तय हुआ कि चार सूत्री मांगों पर 31 जुलाई तक सुनवाई नहीं होने की दशा में चार-पांच अगस्त को जंतर-मंतर नई दिल्ली में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी ने कहा कि पेंशनर 7500 प्रति माह पेंशन महंगाई भत्ता के साथ देने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा पति-पत्नी को निशुल्क इलाज, हायर पेंशन को सुप्रीम कोर्ट के अनुसार लागू करने और ईपीएस से छूटे लोगों को पांच हजार रुपये देने की मांग हो रही है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केएस तिवारी, राष्ट्रीय सलाहकार राजेश शुक्ला ने ज्यादा से ज्यादा पेंशनरों से जंतर-मंतर पर पहुंचने का आह्वान किया। बैठक में अनूप कुशवाहा, जय सिंह सचान, गंगा प्रसाद लोधी, नासिर अली खान, आरपी त्यागी, जय रूप सिंह परिहार, वीपी मिश्रा, चंद्रशेखर पाठक, हनुमान सहाय आदि मौजूद रहे।

भारतीय जनता मजदूर संघ में राष्ट्रीय सचिव मनोनीत हुए - नसीर अली

कानपुर नगर ।भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रभारी एवं भारतीय जनता मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शांत प्रकाश जाटव जी के निर्देश पर कानपुर नगर निवासी श्री नसीर अली की समाज सेवा एवं मीडिया जगत के साथ राष्ट्रहित में कार्य करने में रुचि को देखते हुए भारतीय जनता मजदूर संघ में राष्ट्रीय सचिव पद पर मनोनीत किया गया।

इस मनोनयन से श्री नसीर अली जी के चाहने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई और उनको बधाई का संदेश प्राप्त होने लगा और संघ के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट रक्षपाल सिंह ने मनोनयन पत्र जारी करते हुए संगठन का विस्तार व प्रचार प्रसार करते हुए संगठन को मजबूत बनाने की उम्मीद जताई है और मीडिया से चर्चा के दौरान भारतीय जनता मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया ।

बहुत करीब से देखा है मैंने सबरे खलील, मगर हुसैन अ. तेरे सब्र का जवाब नही

कानपुर,अन्जुमन फिरदौसिया के जनरल सेक्रेटरी तालिब सज्जादी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि आज मोहर्रम की 6 तारीख पर अन्जुमन फिरदौसिया के तत्वाधान में ग्वालटोली मकबरा शिया जामा मस्जिद में कर्बला के नन्हें मुजाहिद और इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे हज़रत अली असगर की शहादत की याद में मजलिसे अजा बरपा हुई । जिसे मौलाना सय्यद तौक़ीर हुसैन साहब ने सम्बोधित करते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि कोई शख्स मरता है तो उसके चेहरे पर रोने के आसार होते हैं लेकिन कर्बला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपने 6 महीने के बेटे हजरत अली असगर जो 3 दिन के भूखे और -प्यासे थे इमाम खेमे से कर्बला के मैदान में अपने हाथों पर लेकर पहुंचे और जालिम यजीदियों से मासूम बच्चे के लिये पानी का मुतालबा किया। इसके जवाब में तीन फल का तीर अली असगर का गला छेदता हुआ इमाम के बाजू में लगा और बच्चा मुस्कुराता हुआ इमाम की गोद में शहीद हो गया। यह बयान सुनकर मजलिस में मौजूद लोगों की आखों से आंसू छलक पड़े। इसके उपरान्त जुलूस झूला अली असगर बरामद हुआ। गश्त के दौरान मातम और सीनाजनी की जा रही थी। इस तरह कर्बला के शहीदों को खिराजे अकीदत पेश किया जा रहा था। इस गम को याद करके यह अजीम हस्तियां आंसू बहाये बिना न रह सकीं। उन्होंने आगे कहा कि एक अवसर पर पैगम्बरे इस्लाम मकामे अबवा पर पहुंचे जहां रसूले इस्लाम की वालिदा की कब्र है रसूले इस्लाम के साथ सहाबा की भारी जमात थी। आखिर हज़रत अपनी वालिदा की कब्र पर बहुत रोये यह मंज़र देखकर सहाबा इकराम भी रोने लगें अबू दाऊद व इब्ने माजा इसके रावी हैं। मौलाना ने आगे कहा कि इमाम आली मकाम के बेटे हज़रत अली अकबर जिनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी इंसानियत और दीने मोहम्मदी को बचाने के लिये कर्बला के मैदान में यजीदी फौजों से जिहाद करते हुए जब घोड़े से नीचे आये तो इमाम को पुकारा बाबा आपको मेरा आखिरी सलाम इमाम पहुंचे तो देखा कि अली अकबर के सीने में बरछी लगी हुई है। इमाम ने दोनों घुटने टेक कर दोनों हाथों से बरछी को खींचा तो बेटे का कलेजा बरछी के साथ निकल आया। यह बयान सुनकर मजलिस में बैठे लोगों की आंखो से आंसू निकलने लगे। इन दोनों जुलूसों में आसिफ अब्बास ,पप्पू मिर्जा, डा0 जुल्फिकार अली रिज़वी, नवाब मुमताज़ हुसैन, नवाब इम्तियाज़ हुसैन, इब्ने हसन ज़ैदी, हसनैन अकबर, नकी हैदर , रानू नकव, मुन्तज़िर हसन, हाजी अख्तर हुसैन,हसनैन असगर,हैदर नक़वी, राशिद ज़ैदी, स. अली आला,शफी अब्बास, वसी हैदर,हसीन हुसैन,सदाक़त हुसैन रिज़वी आदि रहे।

यात्रियों से मोबाइल लूटने वाले शातिर गिरफ्तार, दोनों पर दर्ज हैं आधा दर्जन से अधिक मामले

कानपुर । जीआरपी ने ट्रेनों व सेंट्रल स्टेशन पर यात्रियों का कीमती सामान लूटने वाले दो शातिरों को दबोचा है। इनके कब्जे से लूटे गए 1.75 लाख के तीन मोबाइल बरामद हुए हैं। सभी को जेल भेज दिया गया है। जीआरपी प्रभारी निरीक्षक ओमनारायण सिंह ने बताया कि बुधवार को हैरिसगंज पुल पर चेकिंग के दौरान कुंदननगर अलीगढ़ निवासी संदीप सिंह और दादानगर कॉलोनी निवासी अमित निषाद को गिरफ्तार किया गया ।पूछताछ में पता चला कि दोनों शातिर लुटेरे हैं और ट्रेनों में लूट करते हैं। दोनों पर आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं।

असामाजिक तत्वों पर सख्ती, मोहर्रम जुलूस की सुरक्षा को लेकर पुलिस सतर्क

बीपीएस न्यूज

कानपुर। सातवीं मोहर्रम पर्व पर जुलूस के शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित आयोजन के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। इसी क्रम में गुरुवार को पुलिस उपायुक्त सेन्ट्रल श्री श्रवण कुमार सिंह ने थाना चमनगंज एवं अनवरगंज क्षेत्रों में निकलने वाले जुलूस मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया ।निरीक्षण के दौरान पुलिस उपायुक्त ने आयोजकों और ताजियादारों से संवाद कर दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अपील की कि सभी झंडों की ऊंचाई निर्धारित सीमा के अनुरूप ही रखी जाए, जिससे बिजली के तारों आदि से किसी भी दुर्घटना की संभावना न रहे।श्री सिंह ने कहा कि जुलूस के दौरान सामाजिक सौहार्द और शांति बनाए रखना सर्वोपरि है। किसी भी असामाजिक तत्व की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी तथा आवश्यकतानुसार उनके विरुद्ध त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।उन्होंने बीट उप निरीक्षक और बीट आरक्षियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि संवेदनशील स्थलों पर नियमित गश्त करें, हर गतिविधि पर सतर्क दृष्टि रखें और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान होते ही तत्काल कार्रवाई करें।

पुलिस उपायुक्त ने स्थानीय नागरिकों और धार्मिक आयोजकों से अपील की कि किसी भी अफवाह या भ्रामक सूचना की पुष्टि किए बिना उसे न फैलाएं और किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें ।सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों की सक्रियता, ड्रोन कैमरों के उपयोग और नियंत्रण कक्ष से सतत सम्पर्क बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर सहायक पुलिस आयुक्त अनवरगंज सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

न्याय की ऐतिहासिक जीत: नेत्रहीन महिला को तीन दशक पुराने संघर्ष के बाद मिली अपनी पूरी ज़मीन

कानपुर। तीन दशक पुरानी पीड़ा, अंधकार से भरी ज़िंदगी और हक़ की लौ को जलाए रखने का साहस — इन सबका नतीजा उस दिन सामने आया जब एक नेत्रहीन महिला को अपनी खरीदी हुई ज़मीन पर पूरा कब्ज़ा मिल गया। प्रशासन की तत्परता और मानवीय संवेदनशीलता से यह मामला एक मिसाल बन गया है कि अगर इरादा पक्का हो और व्यवस्था जवाबदेह, तो वर्षों पुराना अन्याय भी खत्म हो सकता है।

यह मामला कल्याणपुर क्षेत्र की एक नेत्रहीन महिला का है, जिन्होंने 30 जून को जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह के जनता दर्शन में अपनी शिकायत प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि उनके दिवंगत पिता ने लगभग तीस साल पहले ग्राम बैरी अकबरपुर बांगर, तहसील सदर स्थित गाटा संख्या 909, रकबा 0.0330 हेक्टेयर भूमि खरीदी थी। लेकिन इस भूमि पर पास-पड़ोस के लोगों ने अवैध कब्ज़ा जमा लिया था, जिसके चलते वह कागज़ों में मालिक होते हुए भी ज़मीन के बड़े हिस्से से वंचित रहीं।

शिकायत में उन्होंने यह भी कहा कि वह स्वयं नेत्रहीन हैं और उनके भाई को गंभीर हृदय रोग है। ऐसे में उस भूमि पर दुकान बनाकर जीविकोपार्जन की योजना ही उनके जीवन का एकमात्र सहारा थी।

जिलाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम सदर को स्थल निरीक्षण व त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। निर्देशों के अनुपालन में 2 जुलाई को एसडीएम सदर अविचल प्रताप सिंह और तहसीलदार विनय द्विवेदी राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे। राजस्व अभिलेखों की पुष्टि व चिन्हांकन के बाद अवैध कब्जा हटवाया गया और संबंधित महिला को उनकी पूरी भूमि पर विधिवत कब्ज़ा दिलाया गया। साथ ही कब्जा करने वालों को भविष्य के लिए सख्त चेतावनी दी गई।

भूमि पर अधिकार मिलने के बाद महिला भावुक हो उठीं। उन्होंने जिलाधिकारी एवं प्रशासन के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि अब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वर्षों बाद उनका जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है।

यह घटना न केवल प्रशासन की संवेदनशीलता को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि न्याय भले देर से मिले, लेकिन यदि भरोसा कायम रखा जाए, तो सच्चाई की जीत ज़रूर होती है।

शांति व्यवस्था के लिए अधिकारियों ने ताजिया स्थलों का किया निरीक्षण

कानपुर। आगामी मोहर्रम पर्व को देखते हुए शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में बुधवार को थाना कोहना क्षेत्र अंतर्गत ताजिया दफन कार्यक्रम के मद्देनज़र सहायक पुलिस आयुक्त कर्नलगंज श्री अमित चौरसिया एवं थाना प्रभारी कोहना द्वारा पुलिस बल के साथ ताजिया जुलूस मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया गया ।निरीक्षण अभियान के दौरान उप जिलाधिकारी (एसडीएम) भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने ताजिया रखने के प्रमुख स्थलों का जायजा लिया और आयोजकों से संवाद कर उनकी आवश्यकताओं एवं सुझावों को सुना।

इस दौरान प्रशासन की ओर से आयोजकों को दिशा-निर्देश दिए गए कि पर्व के दौरान निर्धारित रूट, समय एवं व्यवस्था का पूरी तरह पालन किया जाए। शांति व्यवस्था को लेकर आयोजकों से समन्वय बनाए रखने का भी अनुरोध किया गया।

अधिकारियों ने मौके पर मौजूद पुलिस बल को आवश्यक सतर्कता बरतने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। साथ ही स्थानीय नागरिकों से अपील की गई कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें।

पुलिस विभाग ने आश्वस्त किया कि मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और परंपरागत ढंग से सम्पन्न कराने के लिए सभी जरूरी प्रबंध किए जा रहे हैं।

समस्या समाधान शिविर में समस्याएं लेकर पहुंचे दिव्यांग

कानपुर। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के समस्या समाधान शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क बगिया गेट नंबर 4 में दिव्यांगों ने नौकरी रोजगार पेंशन उत्पीड़न ईलाज व आवास की समस्याओं का समाधान कराने की मांग की है।

पार्टी दो जुलाई को भी शिविर का आयोजन करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार ने कहा कि सभी समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी व सम्बन्धित अधिकारियों से वार्ता कर समस्याओं का समाधान कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि विभागों द्वारा दिव्यांगजनों की समस्याओं का समाधान न होने पर दिव्यांग राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के समस्या समाधान शिविर में आते हैं। जिनकी समस्याओं का समाधान कराने का पूरा प्रयास किया जाता है। हजारों दिव्यांगों को अब तक समस्या समाधान शिविर के जरिए लाभ दिलाया जा चुका है। उत्पीड़न के शिकार दिव्यांगों की रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है, पेंशन की समस्याओं का समाधान हो चुका है। नौकरी, रोजगार व आवास की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है उसके लिए सरकार से मांग की जा रही है।

वीरेन्द्र कुमार ने बताया कि दिव्यांगजन रोजगार के लिए ऋण हेतु राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम के माध्यम से आवेदन करके 20 लख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। रोजगार के लिए जिला उद्योग केंद्र, डूडा के माध्यम से भी ऋण का आवेदन किया जा सकता है। किसी दिव्यांग व्यक्ति को रोजगार के लिए ऋण या अन्य कोई समस्या हो वह शास्त्री नगर सेन्ट्रल पार्क बगिया गेट नंबर 4 में प्रात: 9:00 से 12:00 बजे तक संपर्क कर सकता है। समस्या समाधान शिविर में राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार, जिला अध्यक्ष राहुल कुमार, महिला मोर्चा अध्यक्ष अल्पना कुमारी, वैभव दीक्षित, गुड्डी दीक्षित आदि शामिल थे।

जिलाधिकारी ने स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करते हुए छात्रों का टीका कर किया स्वागत

बीपीएस न्यूज

कानपुर। नगर के समस्त प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों में नए शैक्षिक सत्र की औपचारिक शुरुआत हो गई। लगभग 1.25 लाख नामांकित बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ विद्यालयों की ओर रुख किया, जिससे शिक्षा के प्रति जागरूकता और समर्पण का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत हुआ।

जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने कर्नलगंज स्थित प्राथमिक विद्यालय भैंसिया हाता में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करते हुए नन्हे छात्रों का टीका कर स्वागत किया।

उन्होंने कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पुस्तकें, पेन और चाकलेट आदि भेंट किए।

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने छात्रों से संवाद करते हुए कहा-

बच्चो, मन लगाकर पढ़ाई करें, यही समय है जब आप अपने भविष्य की नींव मजबूत कर सकते हैं।

देश को आप जैसे होनहारों की आवश्यकता है ।जिलाधिकारी ने बताया कि विद्यालय में वर्तमान में 54 छात्र पंजीकृत हैं। उन्होंने बच्चों को संख्या वृद्धि बढ़ाने हेतु प्रधानाचार्य को निर्देशित किया।

उन्होंने कहा कि विद्यालय में दिव्यांग अनुकूल शौचालय, स्वच्छ पेयजल की सुविधा, कायाकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत नगर निगम द्वारा कराया गया।

जिलाधिकारी ने कहा कि मैं समस्त अध्यापकगण, जो वास्तव में मां सरस्वती के प्रतिनिधि हैं, से अपील करता हूं कि वे पूर्ण निष्ठा और समयबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। साथ ही, अभिभावकों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें।

मैं सभी अधिकारियों, शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों को नवशैक्षिक सत्र के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विश्वास है कि शिक्षा विभाग और सहयोगी संस्थाएं मिलकर शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यालयीय सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ करेंगी।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष निदेशालय के समन्वित प्रयासों से सभी विद्यार्थियों को समय पर किताबें और शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे सत्र की शुरुआत व्यवस्थित एवं सकारात्मक ढंग से हुई।

यूपी में मानसून की जोरदार वापसी, 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद हुई तेज बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। सोमवार को कानपुर, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, बाराबंकी, लखनऊ, बरेली, अमेठी, गोरखपुर, बहराइच, बस्ती, मेरठ, बिजनौर और वाराणसी जैसे जिलों में अच्छी बारिश हुई। मेरठ में सबसे ज्यादा 178 मिमी बारिश दर्ज की गई। इस बारिश से पूरे प्रदेश में दिन के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा, 22 जिलों में भारी बारिश और 48 जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। लखनऊ के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार को मध्य और दक्षिणी यूपी के साथ-साथ बुंदेलखंड में अच्छी मानसूनी बारिश होने की संभावना है ।इस साल जून में पूर्वी यूपी में सामान्य से 15त्न कम (92.6 मिमी) और पश्चिमी यूपी में सामान्य से 60त्न अधिक (125.4 मिमी) बारिश हुई। कुल मिलाकर, पूरे प्रदेश में जून में औसतन 106.1 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 11त्न अधिक है। जुलाई में भी सामान्य से ज्यादा बारिश की उम्मीद है। जून में बिजनौर जिले में सबसे ज्यादा 235.8 मिमी बारिश दर्ज की गई।

लखनऊ में रिमझिम बारिश से मौसम सुहाना

सोमवार को राजधानी लखनऊ में भी मानसूनी बारिश का दौर जारी रहा। दो दिनों की राजधानी में हो रही बारिश से अधिकतम तापमान में 6.6 डिग्री की गिरावट आई है।

बालक एवं बालिका माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता पदों पर पदोन्नतियाँ तत्काल की जाए

बीपीएस न्यूज

कानपुर। उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षक संघ पंडित शिव गोविंद मिश्रा, आर्यनगर इ0, आर नगर कालेज, आर्य नगर में बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद संगठन के अध्यक्ष हरिश्चंद्र दीक्षित ने विज्ञप्ति देते हुए बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक एवं उप शिक्षा निदेशक (मा0) के कार्यालय में नोशनल वेतनवृद्धि के प्रकरण लम्बित पड़े हुए हैं तथा वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा अनावश्यक आपत्तियों लगाई जा रही हैं। संगठन की बैठक में वक्ताओं ने रोष व्यक्त किया तथा माँग की है कि पत्रावलियों का निस्तारण तत्काल किया जाये तथा अनावश्यक लगाई गई अनापत्तियों का निस्तारण कराकर उपशिक्षा निदेशक (माध्यमिक) कार्यालय, कानपुर मंडल कानपुर को प्रेषित किया जाये।

प्रोन्नत वेतनमान का प्रकरण जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में साल भर से पड़े हैं जिनका निस्तारण किया जाय तदर्थ अध्यापकों का वेतन भुगतान के साथ-2 उनके अवशेष वेतन का भुगतान किया जाए। शासनादेश दिनाक 28 अप्रैल 2025 के अनुपालन में प्रवक्ता पदो पर बालक एवं बालिका विद्यालयों में लम्बित पदोन्नतियों की जाए। नगर निगम विद्यालयों के शिक्षकों की प्रवक्ता

पदों पर तथा प्रधानाचार्यों का प्रधानाचार्य पद का वेतन भुगतान किया जाए। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के 30 दिन से अधिक कार्यरत रहने की दशा में उन्हें कार्यवाहक प्रधानाचार्य का वेतन दिया जाए।

चयन बोर्ड नियमावली की समाप्ति के पूर्व नियुक्ति प्राप्त करने वाले तदर्थ प्रधानाचार्यों को उनके पद का वेतन दिए जाने की मांग की बैठक में पारित एक सर्वसम्मति प्रस्ताव द्वारा शिक्षक, शिक्षकोओ एवं शिक्षणेतर कर्मियों के जिला विद्यालय निरीक्षक (प्रथम / द्वितीय)को दिए गए ज्ञापनों के समाधान को माँग की है तथा लम्बे समय से लम्बित समस्याओं का समाधान न होने की दशा में धरना-प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। अधिनियम विरुद्ध कार्य करने वाले के विरुद्ध तेज गति से आन्दोलन चलाने का भी निर्णय लिया गया गया है।

बैठक में जनपदीय अध्यक्ष अनिल मिश्रा, मंत्री राजीव शुक्ला, मण्डलीय मंत्री अशोक तिवारी, सम्बद्ध प्राइमरी नेता राजनरायन मिश्र नगर निगम संयोजक मानवेन्द्र दत्त पाण्डेय, नगर निगम संयोजिका कु0 सुन्नी देवी शुक्ला, वित्त विहीन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राधेश्याम मिश्रा, जिलाध्यक्ष अखिलेश

पाण्डेय तथा शिक्षशकर्मियों के प्रदेश महामंत्री शिव बहादुर यादव एवं जिला मंत्री पंकज कुमार वर्मा एवं विशेष आमंत्रित संत कुमार दीक्षित, सुबोध कुमार कटियार, शिव गोपाल सिंह, राजेंद्र विक्रम सिंह, हरि मंगल, शशांक त्रिपाठी, सर्वेश त्रिपाठी, विनोद कुमार यादव, अरविंद यादव, एमपी कटिहार, कामना वर्मा, सरोज सोनकर आदि मौजूद थे मंच संचालन राजीव कुमार शुक्ल द्वारा किया गया।

मेट्रो कार्य कर रही सेम इंडिया ने जलकल को नहीं जमा कराया डाइवर्जन वेस्टेज मैटेरियल

बीपीएस न्यूज

कानपुर। वार्ड 14 जूही पार्षद शालू सुनील कनौजिया ने बताया कि पिछले तीन सालों से मेट्रो के कार्य की फर्म सेम इंडिया द्वारा यूटिलिटी डायवर्सन के दौरान जलकल विभाग के प्लास्टिक पाइप लोहे के पाइप जलकल की संपत्ति को मैट्रो की फर्म सेम इंडिया ने आज तक जलकल को जमा नहीं किया जिसको लेकर पार्षद शालू सुनील कनौजिया ने जलकल के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर यूटिलिटी डायवर्सन में जलकल की सामग्री ना जमा किए जाने की जांच की मांग की थी।

जिस पर जलकल द्वारा मेट्रो कॉरपोरेशन को यूटिलिटी डायवर्सन और खुदाई के दौरान जलकल की तमाम सामग्री को जमा करने को पत्र लिखा इस दौरान पार्षद शालू सुनील कनौजिया ने कहा कि यूटिलिटी डायवर्सन में जलकल के तमाम पाइपों को फर्म द्वारा बेच दिया गया होगा यदि नहीं बेचा गया तो डायवर्सन के आधार पर जलकल की तमाम सामग्री को सेम इंडिया व मेट्रो कॉरपोरेशन जलकल को जमा कराये।

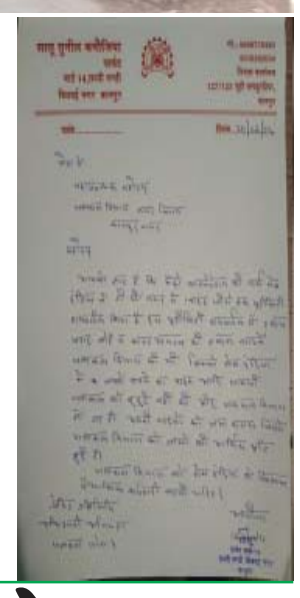

मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने बनाने वालों के खिलाफ होगी कठोरतम कार्यवाही

बीपीएस न्यूज

कानपुर। आम जनमानस को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पनीर उपलब्ध कराये जाने तथा मिलावट पर प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सहायक आयुक्त खाद्य-11 संजय प्रताप सिंह द्वारा विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया।

अभियान के अंतर्गत जनपद के प्रमुख आवागमन मार्गों (नाको) पर अभिसूचना के आधार पर पनीर विक्रय हेतु ले जा रहे वाहनों की गहन जांच तथा पनीर निर्माण/विक्रय इकाइयों से नमूना संग्रहण की कार्यवाही की गई। विशेष अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा विभिन्न स्थानों से पनीर के नमूने संग्रहित किये गये।

कुल 14 नमूनों का संग्रहण कर उन्हें जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया है। अभिसूचना के आधार पर कुल 380 कि.ग्रा. पनीर जब्त/विनष्ट किया गया, जिसका बाजार मूल्य लगभग ? 90,500/- है ।

नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आवश्यकतानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

जिनका विवरण निम्नानुसार है-

1. पनीर कलक्टरगंज, कानपुर नगर - -
2. पनीर न्यू सब्जी मंडी, लाल बंगला - -
3. पनीर गुरूदेव के पास, कानपुर नगर 30 कि.ग्रा. ? 7,200/-
4. पनीर गुरूदेव के पास, कानपुर नगर 90 कि.ग्रा. ? 21,600/-
5. पनीर गुरूदेव के पास, कानपुर नगर 70 कि.ग्रा. ? 16,800/-
6. पनीर न्यू गंगापुल, बिठूर 50 कि.ग्रा. ? 10,500/-
7. पनीर न्यू गंगापुल, बिठूर - -
8. पनीर माल रोड स्थित प्रतिष्ठान - -80 किलो मूल्य 20000 का जब्त किया गया ।
9. पनीर माल रोड स्थित प्रतिष्ठान - -
10. पनीर घाटमपुर स्थित प्रतिष्ठान - -
11. पनीर घाटमपुर स्थित प्रतिष्ठान - -
12. पनीर घाटमपुर स्थित प्रतिष्ठान - -
13. पनीर माल रोड स्थित प्रतिष्ठान - -
14. पनीर केशरवानी, सब्जी मंडी, जनरलगंज 60 कि.ग्रा. ? 14,400/-

सीओ मैडम के कानून का गंदा खेल जनता पर सख्ती, पुलिस पर रहम

बीपीएस न्यूज

उन्नाव। कानून सबके लिए समान है — यह नारा तो हर पुलिस चौकी, हर सरकारी दफ्तर और हर जनसभा में गूंजता है। मगर उन्नाव के सीओ कार्यालय के बाहर का नजारा इस दावे की पोल खोल रहा है। यहां पुलिस लिखी बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियां खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं, और सीओ मैडम की सख्ती का डंडा सिर्फ आम जनता तक ही सीमित नजर आता है। नंबर प्लेट गायब, पुलिस लिखकर नियमों को ठेंगा! हाल ही में सीओ उन्नाव ने एक पत्रकार की गाड़ी सिर्फ इसलिए सीज कर दी, क्योंकि उसकी नंबर प्लेट आंशिक रूप से मिट गई थी। नियमों की यह सख्ती तारीफ-ए-काबिल थी, मगर अब उसी सीओ ऑफिस के बाहर खड़ी दर्जनों बाइकों का सच सामने आया है। इन बाइकों पर नंबर प्लेट की जगह बस पुलिस लिखा है, मानो यह शब्द कानून से ऊपर का पासपोर्ट हो, ये वाहन दिनभर कार्यालय के बाहर खड़े रहते हैं, और न कोई सवाल, न कोई कार्रवाई।

क्या पुलिस का यह खास स्टेटस नियमों से छूट का लाइसेंस बन गया है ?

सीसीटीवी की आंखें, मगर कार्रवाई कुंभकर्णी नींद मे है सीओ कार्यालय के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे इस नंगे उल्लंघन

के मूक गवाह हैं। कैमरे तो दिन-रात सच रिकॉर्ड करते हैं, मगर सवाल यह है कि क्या इन फुटेज को देखने की हिम्मत कोई दिखाएगा? अगर कानून का डंडा चलाना है, तो शुरुआत अपने घर से क्यों न हो? आखिर, जब बात नियमों की हो, तो पुलिस और जनता में भेदभाव क्यों ?

क्या पुलिस लिखने से नंबर प्लेट की जरूरत खत्म हो जाती है? सीओ मैडम की सख्ती सिर्फ आम आदमी के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए नहीं? क्या कानून की किताब में पुलिस वालों के लिए अलग पन्ना छपा है?

यह मामला सिर्फ बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों का नहीं, बल्कि प्रशासन की विश्वसनीयता और निष्पक्षता का है। जब आम जनता पर नियमों का हंटर चलता है, तो पुलिस वालों को पुलिस लिखकर छूट क्यों? अगर सीओ मैडम को सचमुच कानून का पाठ पढ़ाना है, तो शुरुआत अपने दफ्तर के बाहर खड़ी इन बाइकों से करनी होगी। अब सबकी नजरें सीओ उन्नाव पर टिकी हैं उन्नाव की जनता और सोशल मीडिया पर अब सवालों का तूफान उठ रहा है। क्या सीओ मैडम इस खुले उल्लंघन पर एक्शन लेंगी, या यह मामला भी अंदरखाने की छूट में दब जाएगा? क्या कानून का डंडा सिर्फ जनता के लिए है, या पुलिस भी इसकी जद में आएगी? जवाब का इंतजार उन्नाव की गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक बेसब्री से हो रहा है। कानून का असली चेहरा कब दिखेगा? यह वक्त है कि सीओ उन्नाव न सिर्फ अपनी सख्ती का परचम लहराएं, बल्कि यह भी साबित करें कि कानून की नजर में कोई छोटा-बड़ा नहीं। अगर पुलिस लिखी गाड़ियां नियम तोड़ सकती हैं, तो फिर जनता से नियम पालन की उम्मीद कैसे? अब गेंद सीओ

मैडम के पाले में है — क्या वे इस दोहरे रवैये को खत्म करेंगी, या यह कहानी भी पुलिस की गाड़ी, पुलिस का नियम बनकर रह जाएगी? उन्नाव की सड़कों से उठा यह सवाल अब हर उस शख्स की जुबान पर है, जो कानून की निष्पक्षता में यकीन रखता है।

प्राथमिक स्कूलों का विलय, 8 वर्ष बच्ची के साथ दुष्कर्म के विरोध में जिलाधिकारी को ज्ञापन

प्रयागराज में हुई घटना की निष्पक्ष जांच सीबीआई से करने की मांग

बीपीएस न्यूज

कानपुर। सरकार के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों को बन्द किये जाने के विरोध में एवं जनपद कौशाम्बी और प्रयागराज में हुई घटनाओं की निष्पक्ष जांच सी0बी0आई0 से कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश को कानपुर महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ शर्मा विश्वकर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन सोपा।

आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवो0 चन्द्रशेखर आजाद सांसद के निर्देशानुसार 03 जुलाई 2025 को कानपुर कचेहरी स्तिथ कौशिक पार्क से पैदल मार्च करके आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) व भीम आर्मी के कार्यकर्ताओ के साथ जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन पत्र के माध्यम से निम्नलिखित मांग की गई। उ0प्र0 सरकार के द्वारा 27,965 प्राथमिक विद्यालयों को विलय करके बन्द करना यह संविधान के अनुच्छेद 21-ए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और अनुच्छेद 46 (कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों की सुरक्षा) के प्रावधानों का उल्लंघन है।

गरीबों के बच्चों को सरकार के स्कूलों में शिक्षा मिलना अनिवार्य है इसलिए तत्काल ही स्कूल बन्द करने के निर्णय को वापस लिया जाये। जनपद कौशाम्बी के लॉहदा गांव थाना सैनी में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किये जाने की घटना में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने तथा जनपद प्रयागराज के इसौटा गांव थाना करछना में अ0जा0 के व्यक्ति को जिन्दा जलाकर मार देने की घटना में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाये जाने और करछना में पीड़ित परिवार के आरोपियों तथा स्थानीय लोगों के साथ पुलिस के द्वारा पथराव व लाठी चार्ज एवं मोटर साईकिलों को तोड़ना और जलाना एवं इस प्रकरण में सुनील कुमार गौतम उम्र 25 वर्ष के दलित युवक की मृत्यु हो जाने पर उपरोक्त सभी घटनाओं की सी0बी0आई0 द्वारो निष्पक्ष जांच करायी जाये तथा पीड़ितों को न्याय दिलाया जाये।

गांव इसौटा थाना करछना प्रयागराज में इस प्रकरण में पकड़े गये निर्दोष व्यक्तियों को तत्काल रिहा किया जाये एवं शान्ति व्यवस्था हेतु उचित कदम उठाये जाये। ज्ञापन के दौरान महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ शर्मा विश्वकर्मा सुनील कोरी महानगर प्रभारी ओ0पी0 गौतम जिला संयोजक निशांत कुमार, अमन जाटव मंडल संयोजक अभी गौतम जिला संयोजक गौतम महानगर महामंत्री बबली गौतम महानगर कोषाध्यक्ष रामकुमार गौड़ एडवोकेट हबीब आदर्श यादव अब्दुल कादिर अंकित आदि लोग रहे।

70 लाख की चोरी में गोल्ड लोन कंपनी के मैनेजर समेत सात गिरफ्तार

कानपुर। चकेरी क्षेत्र में नकदी समेत करीब 70 लाख के जेवरात चोरी में पुलिस ने गोल्ड लोन कंपनी के मैनेजर समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें दो सराफा करोबारी हैं। उन्होंने गहनों को गलाकर सोने के बिस्कुट में बदल दिया था। वारदात में शामिल एक आरोपी को चोरी के दूसरे मामले में गुजैनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 160 ग्राम जेवर बरामद किए हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस सिर्फ 60 फीसद ही गहने बरामद कर सकी है।रामपुरम निवासी जटाधर दीक्षित के घर से 28 जून की रात को करीब 35 हजार की नकदी और जेवर चोरी हो गए थे। वह परिवार के साथ चित्रकूट गए थे। पड़ोसी के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में सफेद कार नजर आई थी। उसमें सवार तीन युवक 17 मिनट में आते और जाते दिखाई दी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच की। करीब 150 के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई। कार सवार दक्षिण क्षेत्र में दिखाई दी फिर कार का कहीं पता नहीं चला।पुलिसकर्मियों ने कार के नंबर को ट्रेस किया, जिससे असली मालिक की जानकारी हुई। उनसे पूछताछ करने पर हनुमंत विहार के शिवम के बारे में पता चला। शिवम ने कार करीब दो लाख 60 हजार रुपये में खरीदी थी। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से सभी को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम को 25 हजार रुपये के इनाम देने की घोषणा की गई।डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि गिरोह का मास्टरमाइंड बर्रा के कर्रही रोड निवासी हिमांशु गौतम है। वह पूर्व में चोरी के मामले में जेल जा चुका है। उसने कर्रही के रोहन सचान व हनुमंत विहार के शिवम राजपूत और कैंट क्षेत्र के हरिओम के साथ मिलकर चोरी की। कार हरिओम चला रहा था। गिरोह में फर्रुखाबाद के मैरापुर क्षेत्र का रोहित दुबे, उन्नाव के गंगाघाट निवासी संजय सोनी और शिवाला बाजार के निमिष गुप्ता शामिल हैं।

रहस्यमयी कीड़े से दहशत, एक की मौत, काटते ही हो जाता है गायब

अलीगढ़ में एक रहस्यमयी अदृश्य कीड़े को लेकर लोगों में दहशत फैल गई है। स्थानीय रिपोर्ट्स की माने तो ये एक जहरीला कीड़ा है, जिसके काटने से एक महिला की मौत हो चुकी है। वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायल लोगों का कहना है कि यह कीड़ा काटते ही अदृश्य हो जाता है, किसी को दिखाई नहीं देता, काटने के तुरंत बाद तेज जलन, सूजन और चक्कर आने लगते हैं, ये शुरुआती लक्षण अभी तक सामने आ पाए हैं। वहीं स्थानीय डॉक्टरों का मानना है कि यह किसी अज्ञात कीड़े का विषाक्त दंश हो सकता है, जिससे एलर्जी या टॉक्सिक शॉक जैसे रिएक्शन हो रहे हैं।फिलहाल प्राथमिक उपचार में ऐंटीहिस्टामिन और दर्द निवारक दिए जा रहे हैं, अभी तक किसी स्पष्ट कीड़े की पहचान नहीं हुई है।लेकिन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंच चुकी है, क्षेत्र में फॉगिंग और कीटनाशक छिड़काव शुरू कर दिया गया है। साथ ही प्रभावित परिवारों की निगरानी की जा रही है। गांव के लोगों का कहना है कि वे अब बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। वहीं प्रशासन से 24 घंटे मेडिकल सहायता और निगरानी की मांग की गई है।

फिलहाल इस रहस्यमयी कीड़े की असलियत क्या है, यह तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल अलीगढ़ के इस गांव में डर का माहौल गहराता जा रहा है।स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक, एक और किशोरी को कीड़े ने रविवार (29 जून) को काटा। करीब 10-12 दिन पहले एक महिला की मौत भी इसी संदिग्ध कीड़े के काटने के बाद हुई थी। मृतक महिला का नाम मीरा देवी (45 साल) बताया गया। कीड़े काटने के बाद उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। परिजन ने उन्हें तुरंत आगरा रोड पर दो नर्सिंग होम में ले गए, जहां सांप के काटने की संभावना को खारिज कर दिया गया।

इलाज के बावजूद, मीरा देवी की मृत्यु हो गई। तीन और लोग इस कीड़े का शिकार हुए हैं, जिन्हें आनन-फानन में जिला अस्पताल और एक निजी मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है।स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि कीड़ा अभी तक किसी की नजर में नहीं आया है, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पाई है।

सिद्धारमैया का आरोप - कोरोना वायरस की वैक्सीन हो सकती है हार्ट अटैक की जिम्मेदार ?

हाल में युवाओं में दिल का दौरा पड़ने के बढ़ते मामलों पर गहराई से शोध करने की जरूरत है।हालांकि, बदलती जीवनशैली, खानपान और गैर-संचारी बीमारियों को दिल की समस्याओं का कारण माना जाता है, लेकिन हासन में सामने आए मामलों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसका समाधान तलाशने के लिए, विशेषज्ञों की एक टीम को शोध करने और 10 दिन के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने हासन जिले में दिल का दौरा पड़ने के बढ़ते मामलों की जांच के लिए विशेषज्ञों से एक अध्ययन करवाने का आदेश दिया है। सोमवार को 'एक्स' पर पोस्ट कर मंत्री ने कहा कि हासन जिले में एक माह के भीतर दिल का दौरा पड़ने के आए 18 मामलों को स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से लिया है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा हासन जिले में हृदय संबंधी मौतों को कोविड-19 वैक्सीन से जोड़ने के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कई एजेंसियों के माध्यम से अचानक अस्पष्टीकृत मौतों के मामले की जांच की गई है और इन अध्ययनों से यह निर्णायक रूप से स्थापित हो गया है कि कोविड-19 टीकाकरण और अचानक मौतों की रिपोर्ट के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है।

इसमें कहा गया है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) के अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत में कोविड-19 के टीके सुरक्षित और प्रभावी हैं तथा इनमें गंभीर दुष्प्रभावों के मामले अत्यंत दुर्लभ हैं।

कोविड टीके को जल्दबाजी में मंजूरी देना भी दिल के दौरे का कारण हो सकता है- सिद्धरमैया

लेकिन इससे पहले सिद्धारमैया ने मंगलवार (1 जुलाई, 2025) को कहा कि जनता के लिए कोविड-19 वैक्सीन की जल्दबाजी में मंजूरी और वितरण भी इन मौतों का एक कारण हो सकता है। कर्नाटक के हासन में दिल के दौरे से हुई मौतों के हालिया मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मंगलवार को कहा कि जल्दबाजी में कोविड टीके को मंजूरी और लोगों का टीकाकरण करना भी इन मौतों का एक कारण हो सकता है। उन्होंने सभी लोगों से से आग्रह किया कि यदि उन्हें सीने में दर्द या सांस लेने में कठिनाई हो, तो वे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच कराएं और इसे नजरअंदाज न करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अकेले हासन जिले में ही पिछले महीने दिल के दौरे से 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई है।

उन्होंने 'एक्स' पर कहा, सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है। इन मौतों के वास्तविक कारण का पता लगाने और समाधान खोजने के लिए जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च के निदेशक डॉ. रवींद्रनाथ के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई है और उन्हें 10 दिनों के भीतर अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। सिद्धरमैया ने कहा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोविड-19 टीके को जल्दबाजी में मंजूरी देना और लोगों का टीकाकरण करना भी इन मौतों का एक कारण हो सकता है, क्योंकि हाल में दुनिया भर में कई अध्ययनों ने संकेत दिया है कि कोविड टीके दिल के दौरे की बढ़ती संख्या का कारण हो सकते है। इससे पहले कि भाजपा इस मामले को लेकर हमारी आलोचना करे, उन्हें अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए।

भारत में 18-45 वर्ष की आयु के वयस्कों में अस्पष्टीकृत अचानक मृत्यु

आईसीएमआर के राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान (एनआईई) द्वारा किए गए पहले अध्ययन का शीर्षक था भारत में 18-45 वर्ष की आयु के वयस्कों में अस्पष्टीकृत अचानक मृत्यु से जुड़े कारक - एक बहु-केंद्रित मिलान केस नियंत्रण अध्ययन।

बयान में कहा गया है कि यह अध्ययन मई से अगस्त 2023 तक 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 47 तृतीयक देखभाल अस्पतालों में किया गया था।

बयान में कहा गया है कि यह अध्ययन मई से अगस्त 2023 तक 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 47 तृतीयक देखभाल अस्पतालों में किया गया था।

इसमें ऐसे व्यक्तियों को देखा गया जो स्वस्थ प्रतीत होते थे, लेकिन अक्टूबर 2021 और मार्च 2023 के बीच अचानक उनकी मृत्यु हो गई। निष्कर्षों ने निर्णायक रूप से दिखाया है कि कोविड-19 टीकाकरण से युवा वयस्कों में अस्पष्टीकृत अचानक मृत्यु का जोखिम नहीं बढ़ता है। दूसरा अध्ययन, जिसका शीर्षक है युवाओं में अचानक अस्पष्टीकृत मृत्यु के कारणों का पता लगाना, वर्तमान में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली द्वारा आईसीएमआर के सहयोग और वित्त पोषण से किया जा रहा है।

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार यूपी में बड़े पैमाने पर मंदिरों का कराएगी जीर्णोद्धार

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए मंदिरों के बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार और पर्यटन विकास के लिए एक योजना शुरू की है। एक आधिकारिक बयान में शनिवार को यह जानकारी दी गयी।बयान में कहा गया है कि इस योजना के तहत भृगु (बलिया) और दुर्वासा ऋषि (आजमगढ़) के आश्रमों सहित जैन मंदिर का कायाकल्प किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि बयान में कहा गया है कि विशेष रूप से पूर्वांचल के मंदिरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, पर्यटन विभाग ने एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है।

बयान में कहा गया है कि इसमें बलिया में भृगु आश्रम स्थित चित्रगुप्त मंदिर का सौंदर्यीकरण, तेंदुआ पट्टी फरसातार मौजा होलपुर में हनुमान मंदिर परिसर का पर्यटन विकास, बसंतपुर गांव में उदासीन मठ का विकास, आजमगढ़ के महाराजगंज में भैरो बाबा स्थल का पर्यटन विकास और फूलपुर पवई में दुर्वासा ऋषि आश्रम का विकास किया जाना प्रस्तावित है।बयान में कहा गया है कि मऊ जिले में श्री वीरा बाबा ब्रह्म स्थान का पर्यटन विकास, आजमगढ़ के मिश्रापुर में राम जानकी मंदिर का विकास, कन्नौज के सदर में फूलमती देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा।

बयान में कहा गया है कि इसके साथ ही आजमगढ़ के धन्नीपुर, सिंगपुर और बांसगांव में स्वर्गीय संत परमहंस बाबा के स्थल का भी पर्यटन विकास इस योजना में शामिल है। बयान में कहा गया है कि सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

बयान में कहा गया है कि अयोध्या, काशी, और मथुरा जैसे प्रमुख धार्मिक केंद्रों के साथ-साथ राज्य के अन्य प्राचीन मंदिरों और तीर्थ स्थलों को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं।

कबड्डी चैम्पियन की कुत्ते के काटने से दर्दनाक मौत, नहीं लगवाया था एंटी-रेबीज टीका

उत्तर भारत से दिल दहला देने वाली लेकिन चिंताजनक खबर सामने आई है, एक राज्य स्तरीय कबड्डी खिलाड़ी की रेबीज से मौत हो गई। उसे कथित तौर पर एक आवारा पिल्ले ने काट लिया था, जिसे उसने नाले से बचाया था। उत्तर प्रदेश के 22 वर्षीय उभरते कबड्डी खिलाड़ी बृजेश सोलंकी को मौत से कुछ दिन पहले ही रेबीज के लक्षण दिखने लगे थे। राज्य चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता और प्रो कबड्डी लीग के संभावित खिलाड़ी बृजेश को एक आवारा पिल्ले ने काट लिया था, जिसके बाद उसे एंटी-रेबीज वैक्सीन नहीं मिली थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। ऐसा नवीनतम रिपोर्टों में बताया गया है।

सोलंकी के परिजनों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के फराना गांव के निवासी सोलंकी को दो माह पहले एक पिल्ले ने काट लिया था, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया जिसके बाद 28 जून को उसकी तबीयत बिगड़ गई। सोलंकी के भाई संदीप ने बताया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन काफी प्रयास के बावजूद बचाया नहीं जा सका। कबड्डी खिलाड़ी तीन भाइयों में सबसे छोटा था।

संदीप ने बताया, ''करीब दो महीने पहले, एक पिल्ला नाले में फंस गया था। उसे बचाने की कोशिश में पिल्ले ने बृजेश की उंगली पर काट लिया।'' उन्होंने बताया, ''उसने (सोलंकी ने) सोचा कि यह गंभीर नहीं है और उसने एंटी-रेबीज का टीका नहीं लगवाया। बाद में अलीगढ़ के एक निजी अस्पताल ने पुष्टि की कि उसे एक पागल जानवर ने काटा था, संभवत: एक बंदर या कुत्ता।'' बृजेश उस हादसे के दौरान गांव में रह रहा था और स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण ले रहा था। अधिकारियों के अनुसार, उसकी मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर फराना गांव में 29 लोगों को एंटी-रेबीज टीके लगाए हैं।

उनकी मृत्यु के बाद, स्वास्थ्य अधिकारियों ने फराना गांव का दौरा किया और एहतियात के तौर पर कम से कम 29 लोगों को टीका लगाया। स्थानीय जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया है।

पहचान छिपा पंडित जी वैष्णो ढाबा चला रहे सनव्वर और आदिल समेत 5 पर एफआईआर

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित एक ढाबे को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है।

पंडित जी शुद्ध वैष्णो भोजनालय (ढाबा) संचालक पर धार्मिक पहचान छिपाने के साथ-साथ मैंनेजर के साथ मारपीट करने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। बता दें कि यह वही ढाबा है, जहां पैंट उतरवाकर पहचान करने के मामले ने सियासी तुल पकड़ लिया है। ढाबा संचालक का नाम सनव्वर है। सनव्वर के साथ-साथ उसके बेटे आदिल, जुबैर और दो अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

मुजफ्फरनगर में कांवड़यात्रा मार्ग पर स्थित एक ढाबे को लेकर शुरू हुआ पहचान जांच का मामला ने अब नया मोड़ आ गया है।

स्वामी यशवीर महाराज की टीम द्वारा ढाबा मालिकों की जांच के बाद विवाद और तेज हो गया है। अब इस मामले में दोनों पक्षों पर पुलिस कार्रवाई शुरू कर चुकी है, जिससे यह मामला राजनीतिक रंग लेता जा रहा है।

न्यू मंडी थाना क्षेत्र में स्थित पंडित जी वैष्णो ढाबा के संचालक सनव्वर, उनके बेटे आदिल, जुबैर और दो अन्य लोगों पर स्नढ्ढक्रदर्ज की गई है। आरोप है कि इन्होंने ढाबे के पूर्व मैनेजर धर्मेंद्र के साथ मारपीट की। धर्मेंद्र पर आरोप है कि उसने ने ही खुलासा किया था कि हिंदू नाम वाले इस ढाबे का मालिक मुस्लिम है और इसी वजह से सनव्वर उसका बेटा और अन्य ने उनके साथ मारपीट की।

वहीं, दूसरी ओर पुलिस ने बघरा आश्रम के स्वामी यशवीर महाराज के आश्रम से जुड़े छह लोगों को भी नोटिस जारी किया है। जिनमें सुमित बहरागी, रोहित, विवेक, सुमित, सनी और राकेश शामिल हैं। उन्हें तीन दिन के भीतर थाने में पेश होने को कहा गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने प्रशासन की अनुमति के बिना कांवड़ यात्रा मार्ग पर ढाबा मालिकों की पेंट उतरावकर पहचान की थी।

ढाबा के एक कर्मचारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि स्वामी यशवीर महाराज की टीम ने पहचान के नाम पर उससे जबरन पेंट उतारने की कोशिश की थी।

हालांकि, इस आरोप को महाराज ने खारिज करते हुए कहा कि यह उन्हें बदनाम करने की साजिश है। वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य लोगों की पहचान की जा रही है और उन्हें भी नोटिस भेजे जा सकते हैं। प्रशासन इसे गंभीर मामला मानकर सभी कानूनी पहलुओं की जांच कर रहा है।

जनता की कमाई से बना जेपीएनआईसी अखिलेश की संपत्ति नहीं: ब्रजेश पाठक

लखनऊ। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रदेश की जनता को छोटी याद्दाश्त वाला समझते हैं, लेकिन जनता अब जागरूक है और गुमराह नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आपने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (जेपीएनआईसी) को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया था, जबकि यह जनता की गाढ़ी कमाई से बना केंद्र था। हमारी सरकार ने कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर इसे एलडीए को सौंप दिया, ताकि यह संपत्ति आम लोगों की सेवा में लगे। यह आपकी निजी संपत्ति नहीं थी।

उप मुख्यमंत्री ने शनिवार को सपा मुख्यालय से बयान जारी होने के बाद पलटवार करते हुए अखिलेश यादव पर सीधे आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2012 से 2017 तक की सपा सरकार ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जंगल कब्जा, खनन घोटाले और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग को संस्थागत रूप से बढ़ावा दिया। उस कार्यकाल में चारों तरफ भाई-भतीजावाद और अपराधियों का बोलबाला था, जिसका जवाब जनता ने उन्हें दो बार सत्ता से बाहर करके दिया है।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सपा शासन में पार्टी का झंडा लगाकर वन भूमि और जंगलों पर कब्जा किया जाता था। पेड़ काटे गए, जंगल उजाड़े गए। लेकिन आज ऐसे लोगों को जेल भेजा जा चुका है और अब कोई वन भूमि की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता।उन्होंने कहा कि खनन माफिया सपा की सत्ता में खुलेआम सक्रिय थे। रोज खनन मंत्री बदलते थे और पार्टी नेताओं के चरणों में बैठने वालों को खनन मंत्रालय दिया जाता था। यह पूरा विभाग ही लूट और बंदरबांट का केंद्र था।

ब्रजेश पाठक ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के सभी सीएचसी व सरकारी अस्पतालों में कुत्ता, बंदर और सांप काटने तक के इंजेक्शन उपलब्ध हैं, जबकि सपा सरकार के समय अस्पताल तबेला बनकर रह गए थे। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में आज सभी ज़रूरी दवाइयां मुफ्त उपलब्ध हैं।

यह पहले की तरह सिर्फ पोस्टर पर नहीं है।

गोमती रिवर फ्रंट को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना कुछ सौ करोड़ की थी, लेकिन हजारों करोड़ खर्च कर दिए गए। जनता के पैसे की खुली लूट हुई। उन्होंने कहा कि यह परियोजना सपा की आर्थिक अनियमितता और सौंदर्यीकरण के नाम पर लूट का उदाहरण है।

पूर्व सफाईकर्मी का सनसनीखेज दावा, 16 साल तक बलात्कार पीड़ितों के शवों को ठिकाने लगाया

धर्मस्थल मंदिर प्रशासन के साथ काम करने वाले एक पूर्व सफाईकर्मी ने बताया कि लगभग एक दशक बाद वह अपराधबोध और पीड़ितों को न्याय दिलाने की इच्छा के कारण सामने आया है। उसने दावा किया कि ये शव कई महिलाओं और स्कूल छात्राओं के थे, जिनका 1998 से 2014 के बीच धर्मस्थल और आसपास के इलाकों में बलात्कार कर हत्या की गई थी।कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां धर्मस्थल मंदिर प्रशासन के साथ काम करने वाले एक पूर्व सफाईकर्मी ने कई सनसनीखेज दावे किए हैं। व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसे सालों तक बलात्कार पीड़ितों के शवों को जलाने और दफनाने के लिए मजबूर किया गया था। उसने हाल ही में स्थानीय पुलिस से संपर्क कर अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है।इस व्यक्ति ने बताया कि लगभग एक दशक बाद वह अपराधबोध और पीड़ितों को न्याय दिलाने की इच्छा के कारण सामने आया है। उसने दावा किया कि ये शव कई महिलाओं और स्कूल छात्राओं के थे, जिनका 1998 से 2014 के बीच धर्मस्थल और आसपास के इलाकों में बलात्कार कर हत्या की गई थी।

शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ओजस्वी गौड़ा और सचिन देशपांडे ने पुलिस के साथ उसके बयान का ब्योरा साझा किया। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया है कि उसने मानव अवशेषों की तस्वीरें दी हैं, जिन्हें उसने हाल ही में खोदकर निकाला है। ये वही अवशेष हैं जिन्हें उसने सालों पहले दफनाया था।अखबार ने व्यक्ति के हवाले से लिखा है, मैं पुलिस से अनुरोध करता हूं कि मेरे द्वारा दफनाए गए शवों के अवशेष खोदकर निकाले जाएं। करीब 11 साल पहले, मैं अपने परिवार के साथ धर्मस्थल छोड़कर पड़ोसी राज्य में छिपकर रहने लगा। हमें हर दिन यह डर सताता रहता है कि हमें भी मार दिया जाएगा। इस गंभीर मामले पर फिलहाल सरकार की प्रतिक्रिया का इंतज़ार है।पूर्व सफाईकर्मी ने अपनी शिकायत में बताया कि शुरुआत में उसे लगा कि जो शव मिल रहे थे (जिनमें ज़्यादातर महिलाओं के बिना कपड़ों वाले शव थे) वे आत्महत्या या डूबने से हुई मौतें थीं। लेकिन कुछ शवों पर यौन उत्पीड़न, गला घोंटने और अन्य चोटों के निशान थे, जिससे उसे शक हुआ।अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, उसने एक घटना का ज़िक्र किया जिसने उसे हमेशा के लिए परेशान कर दिया, %2010 में कलेरी में पेट्रोल पंप से लगभग 500 मीटर दूर 12 से 15 साल की एक लड़की मृत पाई गई थी।

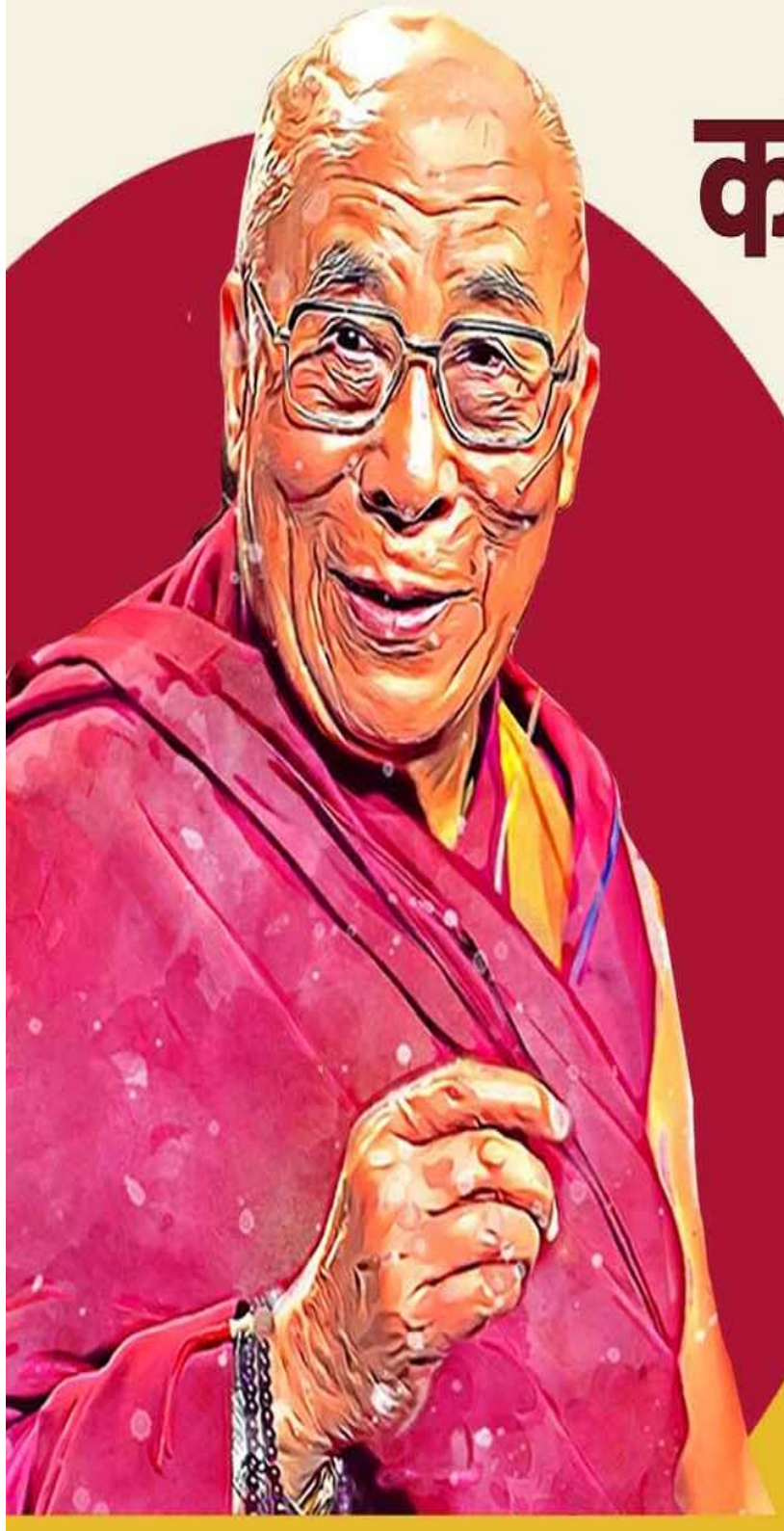

कौन होंगे अगले दलाई लामा?

तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता 14वें दलाई लामा ने पुष्टि की है कि 600 वर्ष पुरानी संस्था उनकी मृत्यु के बाद भी जारी रहेगी, लेकिन उनका उत्तराधिकार केवल धार्मिक मामला नहीं है, यह भू-राजनीतिक विवाद का विषय भी बन सकता है।

कौन हैं दलाई लामा ?

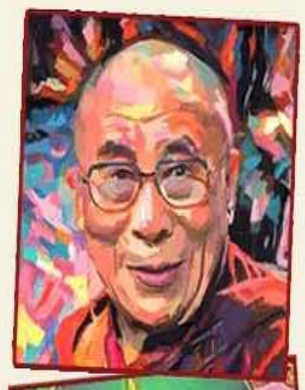

दलाई लामा तिब्बती **बौद्ध धर्म में सर्वोच्च आध्यात्मिक अधिकारी** हैं और तिब्बती पहचान के प्रतीक हैं।

गुंडुन ड्रबड्रब (1391-1474) , जिन्हें गेदुन द्रुपा के नाम से भी जाना जाता है, तिब्बती बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और दलाई लामाओं की वंशावली की शुरुआत का प्रतीक हैं।

वर्तमान दलाई लामा

नाम: तेनजिन ग्यात्सो

जन्म: 6 जुलाई 1935 को, उस समय चीनी सीमावर्ती जिले आमदो के तिब्बती क्षेत्र में

दलाई लामा के रूप में मान्यता: 13वें दलाई लामा की व्यक्तिगत वस्तुओं की पहचान करने के बाद, 2 वर्ष की आयु में

सिंहासनारूढ़: 4 वर्ष की आयु से पहले ल्हासा के पोताला महल में

भारत आये: 1959 में, एक असफल तिब्बती विद्रोह के बाद

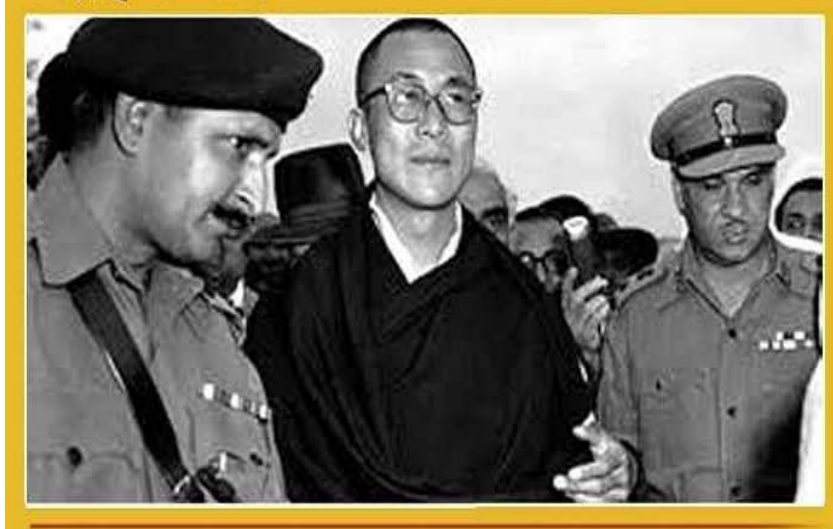

वर्तमान निवास: धर्मशाला, भारत

सम्मान: 1989 में शांति का नोबेल पुरस्कार

दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया

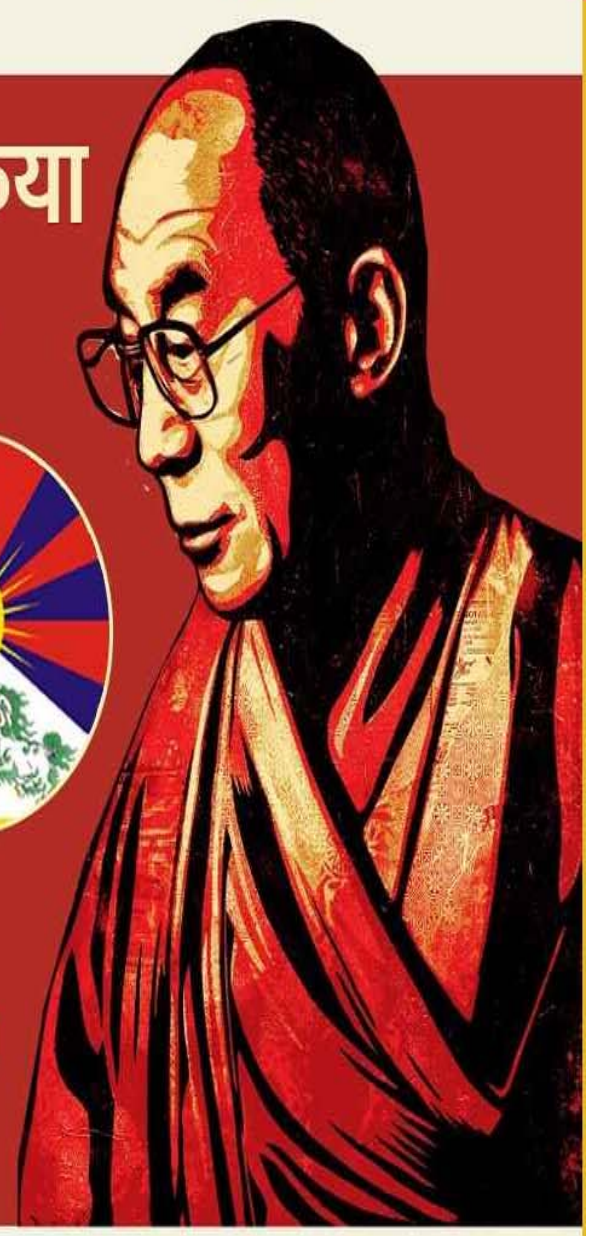

परंपरागत रूप से, दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया पदधारी की **मृत्यु के बाद** ही शुरू होती है।

चयन में निम्न चीजें शामिल हैं:-

- रहस्यमय दर्शन और संकेत
- शगुन और स्वप्न की व्याख्या
- पूर्ववर्ती से व्यक्तिगत वस्तुओं की मान्यता
- बच्चों में आध्यात्मिक गुणों के लिए परीक्षण

इस प्रक्रिया में वर्षों लग सकते हैं और इसका नेतृत्व प्रमुख तिब्बती बौद्ध परंपराओं के **वरिष्ठ भिक्षुओं** द्वारा किया जाता है।

भारत के लिए क्या मायने

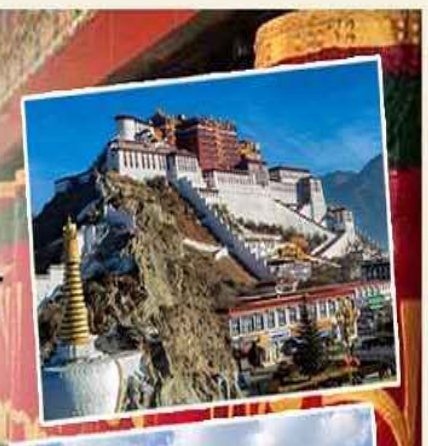

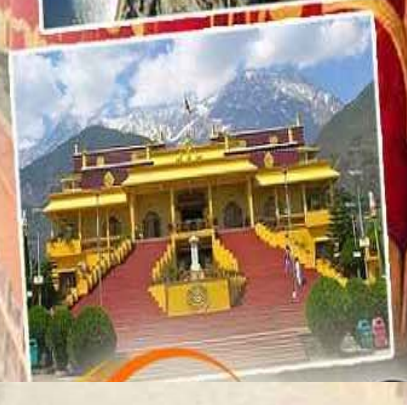

दलाई लामा विश्व स्तर पर सम्मानित आध्यात्मिक नेता हैं और भारत में उनकी उपस्थिति **शांति और अंतर-धार्मिक संवाद** को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करती है।

धर्मशाला में दलाई लामा की मेजबानी करने से चीन के साथ भारत के संबंधों में जटिलता बढ़ गई है, क्योंकि भारत तिब्बत को चीन का हिस्सा मानता है, लेकिन दलाई लामा और उनके अनुयायियों का समर्थन भी करता है।

पुलिस कमिश्नर अधिवक्ता चुनावों में उच्च न्यायालय के निर्देशो का कराए पालन : पं रवीन्द्र शर्मा

बीपीएस न्यूज

कानपुर। लायर्स एसोसिएशन के चुनाव उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कराने को लेकर अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल पुलिस कमिश्नर से मिला। पंडित रवीन्द शर्मा पूर्व अध्यक्ष लॉयर्स एसोसिएशन ने बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अमित कुमार व अन्य की याचिका पर दिशा निर्देश जारी कर अधिवक्ता एसोसिएशन चुनावो में होर्डिंग पोस्टर बैनर पर रोक के साथ साथ, होटल गेस्ट हाउस और पार्टी लानो में आयोजित होने वाले भोज भंडारे और पार्टियों पर भी रोक लगाई किंतु आगामी लायर्स चुनाव के लिए कानपुर कचहरी सहित सम्पूर्ण शहर होर्डिंग पोस्टर बैनरो से पटा पड़ा है।

होटलों गेस्ट हाउसो पार्टी लानो में दिन रात भोज भंडारे और पार्टियां आयोजित की जा रही है। जिनमें बाहरी व्यक्तियों/अपराधियो के शामिल होने की भी चर्चाएं है। ये सारे कार्य उच्च न्यायालय के निर्देशो के प्रतिकूल होने के साथ ही अत्यधिक धन का प्रदर्शन कर सामान्य अधिवक्ता को चुनाव से बाहर रखने की सोची समझी साजिश है। इससे अधिवक्ताओं की छवि भी धूमिल होती है।

शर्मा ने कहा कि लायर्स चुनाव उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हों जिसके लिए आप बिना अनुमति शहर भर में लगे होर्डिंग पोस्टर बैनरो को हटवाते हुए हो रहे भोज भंडारे और पार्टियों पर रोक लगा चुनाव को अधिवक्ता गरिमा के अनुरूप कराना सुनिश्चित करें। पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने पत्र प्राप्त कर कहा कि हम शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करते हुए मा उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशो का पालन करायेंगे। प्रमुख रूप से भानु प्रताप द्विवेदी, अरविंद दीक्षित, प्रशांत शुक्ला, वीर जोशी, योगेश कुमार, इंद्रेश मिश्रा, प्रियम जोशी आदि रहे।

अफवाह या भ्रामक सूचना की सत्यता की पुष्टि किए बिना उसे न फैलाएं –पुलिस उपायुक्त दक्षिण

बीपीएस न्यूज

कानपुर। मोहर्रम के अवसर पर पुलिस उपायुक्त दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी द्वारा पर्व के शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं सुरक्षित आयोजन हेतु व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया। पुलिस उपायुक्त द्वारा नौबस्ता थाना क्षेत्र मछरिया–बसंत विहार–यशोदा नगर से कर्बला नौबस्ता तक निकलने वाले जुलूस मार्ग का भ्रमण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस बल की ड्यूटियों की समीक्षा की एवं मौके पर उपस्थित अधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान किए। मौके पर एसीपी नौबस्ता मौजूद रहे।

पर्व के दौरान सामाजिक सौहार्द बनाए रखने व समन्वय बेहतर रखने हेतु ताजियादारों से सहयोग की अपील की।

?पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया कि वे संवेदनशील स्थलों पर नियमित गश्त करते हुए हर गतिविधि पर सतर्क दृष्टि बनाए रखें एवं असामाजिक तत्वों की पहचान होते ही कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

स्थानीय नागरिकों एवं धार्मिक आयोजकों से भी आग्रह किया गया कि किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना की सत्यता की पुष्टि किए बिना उसे न फैलाएं तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

पुलिस उपायुक्त द्वारा जुलूस मार्ग पर सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायज़ा लेते हुए यह सुनिश्चित किया कि सम्पूर्ण आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न हो।

वर वधू परिचय सम्मेलन में 21 जोड़े शादी को हुए तैयार, सामूहिक विवाह 7 अक्टूबर को होगा सम्पन्न

बीपीएस न्यूज

कानपुर। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महर्षि वाल्मिकी जन्मोत्सव केंद्रीय मेला कमेटी द्वारा वाल्मिकी उपवन मोती झील कानपुर में 28 वा वर वधू परिचय सम्मेलन में 21 जोड़ो ने शादी हेतु तैयार हुए। परिचय सम्मेलन में कुल 163 लड़के समारोह में/लड़कियों ने 7 अक्टूबर को होने वाले सर्व समाज सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा ।

मुन्ना हजारिया ने बताया कि परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है जो समाज में गरीब असहाय लोग हैं जिनकी गरीबी के चलते अच्छे परिवार मिलना असंभव है। कमेटी ऐसे परिवार को ढूंढ कर परिचय सम्मेलन कराकर परिवार के आमने–सामने बातचीत करवा के दोनों परिवारों की सहमति से बात आगे चलती है।महर्षि वाल्मिकी जन्मोत्सव केंद्रीय मेला कमेटी द्वारा आयोजित सर्व समाज सामूहिक विवाह परिचय सम्मेलन मोती झील वाल्मीक उपवन में हुआ। महर्षि वाल्मिकी जन्मोत्सव केंद्रीय मेला का सामूहिक विवाह का आयोजन 7 अक्टूबर को मोती झील कानपुर में सम्पन्न् होगा।

जिसमें 21जोड़ो ने अपने परिवार की सहमति से इस विवाह समारोह मे शादी हेतु तैयार हुए। वर वधू पक्ष के दोनों ओर से सहमति प्रदान की। मुख्य रूप से बृजेंद्र मकोरिया, सतीश वाल्मिकी, प्रकाश हज़ारिया, रामस्वरूप, मुन्ना हजारिया, मुन्ना पहलवान, मुकेश वाल्मिकी, दिनेश सुदर्शन, धर्मेंद्र सेठ, प्रधान, जागे हज़ारियां, आदि मौजूद रहे।

कोई भी वाहन ओवरलोड न हो और सभी वाहनों के नंबर साफ़–साफ़ दिखाई दें :मण्डलायुक्त के. विजयेन्द्र पाण्डियन

कानपुर। मण्डलायुक्त के. विजयेन्द्र पाण्डियन की अध्यक्षता में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक शिविर कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक में जनहित और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने, नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने और लंबित परमिट प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा की गई।

मण्डलायुक्त ने निर्देश दिया कि जिन रूटों पर अभी सार्वजनिक बसें नहीं चल रही हैं, वहाँ बस संचालन की संभावना तलाशी जाए और ज़रूरत के अनुसार प्रस्ताव तैयार किए जाये। सिटी बसों की संख्या बढ़ाने और 28 सीटर बसों के संचालन का निर्णय लिया गया है। साथ ही जहां आवश्यकता हो, वहाँ अनुबंध के माध्यम से बसें चलाई जाये जिससे लोगों को बेहतर और नियमित परिवहन सुविधा मिल सके।

उन्होंने प्रवर्तन की कार्रवाई को तेज़ करने और उसमें आधुनिक तकनीक के उपयोग पर ज़ोर दिया। स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जिन वाहन चालकों के खिलाफ तीन या उससे अधिक बार चालान हो चुके हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने हेतु अभियान चलाया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी वाहन ओवरलोड न हो और सभी वाहनों के नंबर साफ़–साफ़ दिखाई दें। बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में ओवरलोडिंग के कारण 7 वाहनों का पंजीकरण पहले ही निरस्त किया जा चुका है। मण्डलायुक्त ने कहा कि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 84 के अंतर्गत परमिटों की जो शर्तें निर्धारित हैं, उनके उल्लंघन की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी।परिवहन प्राधिकरण द्वारा यह भी बताया गया कि स्थायी स्टेज कैरिज, कानपुर नगर बस परमिट, स्कूल बसों, वैन, टेम्पो और ऑटो रिक्शा के वे परमिट जिनकी वैधता पाँच वर्ष से अधिक समय पूर्व समाप्त हो चुकी है और जिनका नवीनीकरण नहीं कराया गया, उन प्रकरणों पर विचार कर परमिट निरस्तीकरण का निर्णय लिया गया है। अब तक ऐसे कुल 3430 वाहनों का पंजीकरण निरस्त किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त, जिन बसों का संचालन अन्तर्सम्भागीय मार्गों पर बिना प्रतिहस्ताक्षर कराए किया जा रहा था, उन मामलों में यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित परमिटधारकों से शमन शुल्क और प्रतिहस्ताक्षर शुल्क जमा कराने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मण्डलायुक्त ने कहा कि बिना परमिट वाहन चलाना पूरी तरह अवैध है और इस पर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। सभी वाहन स्वामियों को नियमानुसार कार्य करना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (नगर) डॉ. राजेश कुमार, उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) कानपुर आर.आर. सोनी, आरटीओ प्रशासन राकेन्द्र कुमार सिंह, आरटीओ प्रवर्तन राहुल श्रीवास्तव, एआरएम रोडवेज रामलवट तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

आवास विकास की जनता ने की स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की मांग

कानपुर। नौबस्ता, आवास विकास की जनता ने जलकल द्वारा की जा रही बदबूदार पेयजल आपूर्ति को लेकर प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। क्षेत्रीय ने आरोप लगाते हुए बताया कि घर के सामने लगा हैंडपंप पीला पानी उगल रहा है। इसके साथ ही जोन 2 जलकल द्वारा की जा रही बदबूदार पानी की सप्लाई से लोग दो बूंद पानी को तरस रहे है।क्षेत्रीय जनता के मुताबिक बीते करीब 6 माह से क्षेत्र में बदबूदार पानी की सप्लाई से घरों में लोग बीमारी का शिकार हो रहे है।अधिकारियों एवं क्षेत्रीय पार्षद से शिकायत करने के बावजूद किसी ने सुनवाई नहीं की। जनता ने समस्या का समाधान न होने पर जोन जलकल कार्यालय में प्रदर्शन कारण का अल्टीमेटम दिया।

बीपीएस न्यूज क्षेत्रीय कार्यालय में किया गया वृक्षारोपण

कानपुर। बाबू पुरवा कालोनी गेट नंबर 6 चौराहे के पास स्थित बीपीएस न्यूज क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर क्षेत्रीय लोगों के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। क्षेत्र के जागरूक लोगो ने कहा पेड़ लगाना आवश्यक है। क्योंकि वे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और वायु की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। पेड़ों की संख्या बढ़ाने से पर्यावरण में रहने के लिए सुरक्षा बढ़ती है। पेड़ पौधे प्रदूषण को कम करने में भी मदद करते है।जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित होता है। पौधा लगाने में संतोष गुप्ता, पंकज शर्मा, ब्रजेश, अमरनाथ शुक्ल, मनीष शर्मा, गोपाल, आशीष शर्मा आदि लोगों ने सहयोग किया।

विज्ञापन कार्यालय-130/
4 - बाबू पुरवा कॉलोनी,
किदवई नगर, कानपुर

नवीन गुप्ता
(विज्ञापन प्रतिनिधि)

बीपीएस न्यूज समाचार पत्र व ऑनलाइन न्यूज चैनल (पोर्टल) में विज्ञापन लगवाने के लिए संपर्क करें। मो. 9839625941

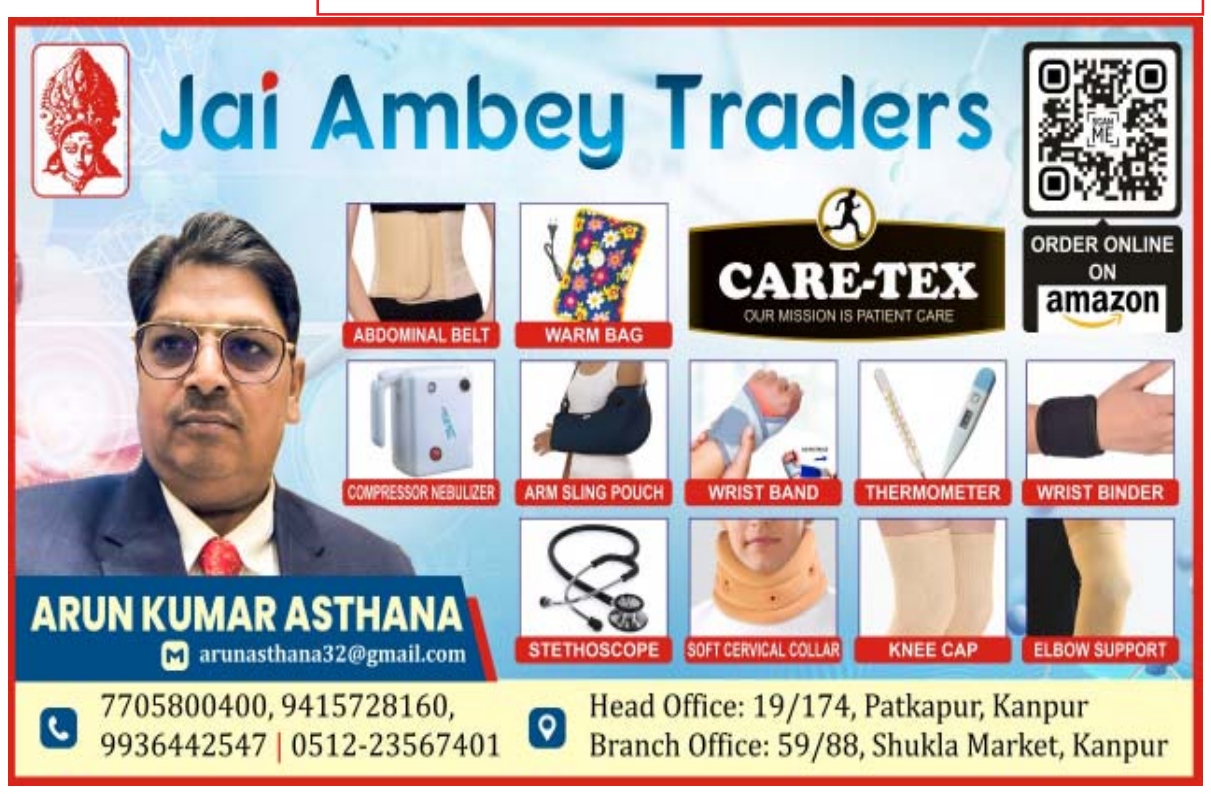

बी पी एस न्यूज
हिन्दी साप्ताहिक

मुद्रक प्रकाशक स्वात्वाधिकारी बुद्ध प्रकाश साहू द्वारा मां प्रिन्टर्स गार्डेन नं. 6–ए/7 रेल बाजार कानपुर नगर से मुद्रित एवं 344– बगाही भट्ठा टी.पी. नगर कानपुर से प्रकाशित। आर.एन.आई. नं. UPHIN/ 2016/ 66740, डाक पंजीयन सं. कानपुर सिटी 304/2024-2026, सम्पादक बुद्ध प्रकाश साहू मो.: 8423454502 , व्हाट्सअप 9335908846 email:bps.knp786@gmail.com info@bpsnews.in www.bpsnews.in नोट–समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र कानपुर नगर न्यायालय होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त लेखों एवं समाचारों की जिम्मेदारी लेखकों व संवाददाताओं की होगी। कृपया कोई भी आपत्ति हो तो 15 दिनों के अंदर भेजें।